



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2007/पौष 5, 1929

No. 381]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2007/PAUSA 5, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2007

अंतिम जांच परिणाम

विषय : यूरोपीय संघ, जापान, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/25/2006-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं को अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए ;

क. पृष्ठभूमि

2. यतः, उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ (ईयू), जापान, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध उत्पाद/वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन की दिनांक 21 सितम्बर, 2001 को पाटनरोधी जांच शुरू की थी। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्राधिकारी की दिनांक 14 दिसम्बर, 2001 के प्रारंभिक जांच परिणामों के आधार पर सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 17/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 11 फरवरी, 2002 के माध्यम से अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम दिनांक 19 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित हुए थे और दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं. 120/2002-सीमाशुल्क के जरिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

3. यतः संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि., चेन्नई द्वारा प्रस्तुत उचित रूप से प्रमाणित आवेदन के आधार पर प्राधिकारी ने यह जाँच करने के लिए कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के पुनः प्रारंभ होने या जारी रहने की संभावना है, अधिनियम की धारा 9क(5) के तहत दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना के जरिए संबद्ध देश के मूल के संबद्ध उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू की थी ।

4. और यतः, दिनांक 6 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 12/2007-सीमाशुल्क के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा धारा 9क(5) के तहत निश्चयात्मक शुल्क को 10 फरवरी, 2008 तक एक वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा गया था ।

## ख. प्रक्रिया

5. नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-

(i) नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार प्राधिकारी ने समीक्षा जाँच शुरू करने से पूर्व आवेदक से पूर्णतः प्रलेखित आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया;

(ii) नियम 6(2) के अनुसरण में प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, उद्योग एसोसिएशनों, संबद्ध देशों के दूतावासों तथा आवेदक को अग्रेषित की गई और उन्हें अपने विचार से लिखित में आवगत कराने का अवसर भी दिया गया;

(iii) संबंधित नियम 6 के उप-नियम (4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा संगत प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी ।

(iv) नई दिल्ली में सम्बद्ध देशों के दूतावासों को जाँच शुरूआत के बारे में सूचित किया गया और उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित अवधि में प्रश्नावली के उत्तर भिजवाने की सलाह देने का अनुरोध किया गया ।

(v) प्राधिकारी ने सूचना माँगने के लिए सम्बद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली सूचनार्थ भेजी थी :

- शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि०, सिंगापुर
- बायर पॉलीयूरेथेन एशिया (पीटीई) लि०, सिंगापुर
- सैन्यो केमिकल्स, जापान
- बायर पॉलीयूरेथेन एशिया (पीटीई) लि०, जर्मनी
- रेफ्सोल क्विमिका, एसए, मैड्रिड, स्पेन
- डो केमिकल्स कं०, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका

केवल सिंगापुर के दो निर्यातकों अर्थात् शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम पीटीई लि० तथा बीएएसएफ साउथ-ईस्ट एशिया पीटीई लि० ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है ।

(vi) आयातक प्रश्नावली के साथ जाँच शुरूआत अधिसूचना की प्रति आवेदन में सूचीबद्ध विभिन्न आयातकों को भी भेजी गई थी ।

- फेयर फोम इण्टरप्राइजेज प्रा०लि०, सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली
- नैट्सन फोम विनिर्माण प्रा०लि०, अहमदाबाद, गुजरात

- ड्यूरा फोम उद्योग प्रा०लि०, सिलवासा, दादरा-नगर हवेली
- सूर्या फोम, पाँडिचेरी
- डीपी फोम प्रा०लि०, पाँडिचेरी/पुडुच्चेरी
- कर्ल-ऑन लि०, बंगलौर, कर्नाटक
- अपर्णा पॉली प्रोडक्ट्स लि०, जयपुर, राजस्थान
- तिरुपति फोम्स लि०, अहमदाबाद, गुजरात
- सॉफ्ट फोम इंडस्ट्रीज प्रा०लि०, आर.आर. जिला, आंध्र प्रदेश
- मद्रास पॉलीमोल्ड्स, चेन्नई, तमिलनाडु
- शीला फोम प्रा०लि०, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
- जे.जे. फोम्स प्रा०लि०, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
- एमएच पॉलिमर्स प्रा०लि०, लि०, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

तथापि, प्रारंभिक गलियों के संशोधन के पश्चात् सम्पूर्ण उत्तर केवल मै० डीपी फोम्स, पुडुच्चेरी से प्राप्त हुआ था। मै० शीला फोम ने अनुरोध किए जाने के बावजूद समर्थक दस्तावेजों के बिना केवल आंशिक उत्तर प्रस्तुत किया था और इसलिए उनके अभ्यावेदनों के अस्वीकार कर दिया गया था।

(vii) व्यापक परिचालन के लिए जाँच शुरूआत अधिसूचना की प्रतियाँ फिक्की, सीआईआई, एसोचेम, एक्साइज लॉ टाइम्स आदि को भी भेजी गई थीं।

(viii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस) से पिछले तीन वर्षों तथा जाँच अवधि के आयात के व्यौरों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था।

(ix) पाटन एवं क्षति की जाँच 1 अप्रैल, 2005 से शुरू करके 30 जून, 2006 तक की अवधि (जिसे जाँच अवधि या पीओआई भी कहा गया है) हेतु की गई। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जाँच हेतु 1 अप्रैल, 2002 से जाँच अवधि (पीओआई) को (जिसे क्षति अवधि भी कहा गया है) शामिल किया गया।

(x) प्राधिकारी ने पाटन एवं परिणामी क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सूचना की माँग की एवं उसका सत्यापन किया। प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग की मौके पर जाँच की। इस बात के अभिनिश्चय के लिए कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति दूर करने की दृष्टि से पर्याप्त होगा; सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर इष्टतम उत्पादन लागत तथा भारत में संबंध वस्तुओं के निर्माण व बिक्री संबंधी लागत निकालने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का विश्लेषण भी किया गया था।

(xi) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 13 अगस्त, 2007 को एक सार्वजनिक सुनवाई की जिसमें घरेलू उद्योग व निर्यातक एवं आयातक उपस्थित हुए थे। सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित हितबद्ध पक्षों से मौखिक रूप में व्यक्त उनके विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने इन जाँच परिणामों में हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित विवरण तथा उनके उत्तरों पर विचार किया है।

(xii) मामले के अनिवार्य तथ्यों को सभी हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष गोपनीय तथा सामान्य प्रकटीकरण के रूप में प्रकट किया गया था। प्रकटीकरण विवरण के बारे में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर, जिस सीमा तक वे सुसंगत थी तथा साक्ष्य द्वारा समर्थित थी, प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

(xii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपान्तर को स्वयं द्वारा रखी जाने वाली सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा। इस अधिसूचना में \*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना को दर्शाता है जिसे प्राधिकारी द्वारा पात्रता संबंधी नियमों के तहत गोपनीय माना गया है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद एवं “समान” वस्तु

6. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में यथापरिभाषित संबद्ध देशों के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित एक पॉलीमर, फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल है। यह एफएसपी 3000-4000 आणविक भार वाला पारदर्शी, चिपचिपा द्रव है जिसका विनिर्माण ट्रायोल श्रृंखला स्टार्टर के साथ प्रॉपीलीन ऑक्साइड एवं इथिलीन ऑक्साइड के पॉलीमराइजेशन से किया जाता है। यह एक पॉलीईथर है और उत्प्रेरकों एवं संयोजियों के साथ इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पॉलीयूरेथेन बनता है जिसका प्रयोग कमरे के साज-सामान, गद्दों, तकियों, मसनदों, परिवहन साधनों में बैठने की व्यवस्था तथा पैकेजिंग में होता है। एफएसपी का स्थानांतरण टैंकरों में किया जाता है या उसका भण्डारण इस्पात के ड्रमों में होता है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 में “प्लास्टिक्स एवं उसकी वस्तुओं” की श्रेणी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 3907.20 के तहत वर्गीकृत है।

7. इस जाँच के समीक्षा जाँच होने के कारण जाँच का दायरा मूल जाँच में अभिज्ञात किए गए उत्पाद तक सीमित है। विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के मुद्दे पर किसी हितबद्ध पक्षकार ने कोई तर्क नहीं दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित उत्पादों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि ये दोनों नियमावली के अर्थ के भीतर “समान वस्तुएँ” हैं।

#### घ. घरेलू उद्योग की स्थिति

8. घरेलू उद्योग की ओर से मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि०, एकल घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत उपयुक्ततः प्रमाणित अनुरोध के आधार पर निर्णायक समीक्षा शुरू की गई है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ मै० मनाली पेट्रोकेमिकल्स घरेलू उद्योग हैं।

#### ड. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

##### क) शुरूआत के संबंध में

9. यूरोपीय आयोग ने यह कहते हुए उपायों को ईयू से निर्यातों पर लागू किए बिना जाँच समाप्त करने का अनुरोध किया है कि समीक्षाधीन उपाय उन 27 उपायों में से थे जो डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन होने के कारण डीएसयू परामर्शों के अध्याधीन थे और भारत के साथ अनुवर्ती परस्पर समझौता

होने के कारण विवाद निपटान पैनल हेतु अनुरोध नहीं किया गया था। यद्यपि अधिकांश उपाय अब लागू नहीं थे, तथापि इसी को अन्य उपायों के भी समाप्त हो जाने की आशा थी और जाँच शुरूआत से उसे निराशा हुई थी जिसका तात्पर्य यह था कि कानूनन गैर जरूरी उपायों की अब समीक्षा की जा रही थी और संभवतः उन्हें जारी रखा जाना था। इसके अतिरिक्त इसी ने कहा है कि जाँच शुरूआत अधिसूचना से घरेलू उद्योग को क्षति की समाप्ति की पुष्टि हुई थी और समीक्षा हेतु अनुरोध में उपायों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों में वृद्धि की पूर्वापेक्षा से प्रेरित क्षति के पुनः प्रारंभ होने की संभावना के युक्तियुक्त साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। तथापि, प्राधिकारी ने नोट किया था कि घरेलू उद्योग ने इस पर विहित कानूनी ढाँचे के भीतर कार्यवाही की है और ईयू से इतर क्षेत्र इसमें शामिल थे और इसलिए उन्होंने जाँच को जारी रखने की अनुमति दी थी।

10. सार्वजनिक सुनवाई में अपने अभ्यावेदनों में सिंगापुर के मै0 शेल ईस्टर्न पीटीई लि0 (जिसे एतदपश्चात् सीईपीएल कहा गया है) ने इस आधार पर समीक्षा की शुरूआत का विरोध किया कि घरेलू उद्योग समीक्षा हेतु मामले को स्थापित नहीं कर पाया था और उसे काफी समय से रक्षोपाय एवं पाटनरोधी शुल्कों की सुरक्षा प्राप्त थी। कि वर्तमान जाँच भेदभावपूर्ण, गैर कानूनी ढंग से शुरू की गई तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम (जिसे एतदपश्चात् सीटी अधिनियम कहा गया है) के दायरे के बाहर थी और उसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए था। उत्तर में घरेलू उद्योग ने माना कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने निर्धारित अवधि के भीतर जाँच शुरूआत के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की थी और इसलिए उसे जाँच में बाधा डालने के लिए बाद में आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस तकनीकी आपत्ति का विरोध मै0 डीपी फोम (जिसे एतदपश्चात् डीपीएफ कहा गया है) द्वारा किया गया था क्योंकि न तो सीटी अधिनियम में और न ही एडी नियमावली में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदनों पर कोई रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, एडी विधान के किसी भी उपबंध में प्रस्तुत याचिका पर आपत्ति करने या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से सहयोगी पक्षकार को रोका नहीं गया है। इन सबके अलावा, एसईपीएल ने निवेदन किया है कि यदि किसी पाटनरोधी जाँच में किसी विशेष तारीख तक कानूनी अभ्यावेदन किया जाना आशयित था तो प्राधिकारी द्वारा एक समाप्ति की रिकॉर्ड तारीख उपलब्ध कराया जाना था जो ऐसी प्रक्रिया या प्रथा नहीं थी जिसका भारत में पालन किया जाता था। प्राधिकारी ने नोट किया कि सभी पक्षकारों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर दिए गए थे।

#### (ख) निर्यातकों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे के संबंध में

11. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि संबद्ध देशों के निर्यातक, निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का सार्थक सारांश प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं; अगोपनीय रूपान्तर अपूर्ण एवं अपर्याप्त है और उन्होंने किसी औचित्य के बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। अतः, व्यक्तिगत व्यवहार को अस्वीकार करके उन्हें असहयोगी माना जाए। इसके अतिरिक्त, यदि गोपनीयता हेतु अनुरोध गैर-जरूरी था और आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में उसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने के प्रति अनिच्छुक था, तो ऐसी सूचना को अस्वीकार किया जा सकता था। एसईपीएल ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने उक्त जाँच में पूरा सहयोग किया है और यह घरेलू उद्योग था जिसने शुरूआती चरण में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करके जाँच को निरर्थक कर दिया था। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के पास उत्तर के गोपनीय रूपान्तर के घटकों की जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि प्रस्तुत आँकड़े विस्तीय प्रकृति के थे और जाँच प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं संवेदनशील आँकड़ों की गोपनीयता में अंतर था।

12. तथापि, प्राधिकारी ने नोट किया था कि बीएसएसएफ-दक्षिण-पूर्वी एशिया पीटीई लि० (जिसे एतदपश्चात् बीएसईए कहा गया है) ने बाद में घरेलू उद्योग द्वारा उनके लिखित अभ्यावेदनों में दर्शाए गए प्रश्नावली के उत्तर में अंतरालों का अगोपनीय रूपान्तर प्रस्तुत किया था जबकि एसईपीएल ने यह दावा करते हुए ऐसा नहीं किया था कि वे अपेक्षित समस्त उत्तर प्रस्तुत कर चुके हैं।

### ग) उत्पादन पद्धति के संबंध में

13. एसईपीएल ने कहा है कि पीओ तथा एफएसपी के उत्पादन की व्यापक रूप से तीन पद्धतियाँ हैं - (i) एसएमपीओ, (ii) क्लोरोहाइड्रीन और (iii) एमटीबीई - जिनमें से प्रत्येक का उत्पादन एवं आर्थिक तौर-तरीका अलग-अलग है। उसका विनिर्माण लागत केन्द्र, शेल केमिकल्स सेराया पीटीई लि० (जिसे एतदपश्चात् एससीएसएल कहा गया है) जिसकी अन्य बातों के साथ-साथ पीओ की दर्शाई गई क्षमता 160 केटी है, एसएमपीओ पद्धति का प्रयोग करता है जो कि एसईपीएल की स्वामित्व वाली पद्धति है, जबकि 24 केटी पीओ की कुल स्थापित क्षमता के साथ घरेलू उद्योग क्लोरोहाइड्रीन मार्ग पद्धति का प्रयोग करता है। क्लोरोहाइड्रीन पद्धति की तुलना में एसएमपीओ पद्धति में अधिक कुशल परिवर्तन पद्धति, बेहतर उत्पादन एवं कम अपशिष्ट उत्पाद जिससे कम कठोर उपचार की आवश्यकता होती है, के लाभ हैं। इसके अतिरिक्त, उत्पाद संभार तंत्र को इष्टतम बनाने के लिए एसएमपीओ निवेश का क्रैकर्स के साथ एकीकरण किया जाता है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि एसईपीएल यह कह कर प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था कि पीओ और एफएसपी के उत्पादन के लिए एसएमपीओ पद्धति का प्रयोग किया जाता है जबकि एसएमपीओ पद्धति का प्रयोग केवल पीओ के उत्पादन के लिए होता है, एफएसपी के लिए नहीं जिसके लिए विनिर्माण पद्धति विश्वभर में एक ही है। एसईपीएल ने प्रकटन के बाद की अपनी टिप्पणियों में प्राधिकारी को गुमराह करने के आरोप का खण्डन किया है।

### घ) तुलनात्मक लाभों के संबंध में

14. एसईपीएल ने कहा है कि उनकी मूल सामग्री पेट्रोसायन हैं और सिंगापुर में पेट्रोसायन संयंत्रों की संख्या ज्यूरॉंग द्वीप में अधिक थी जो सामूहिक रूप से एक समेकित, पाइपलाइन से जुड़े संयंत्रों, परसम्पत्तियों एवं अनुप्रयोज्यताओं को दर्शाता है। एसईपीएल समय एवं प्रयास या वास्तविक प्रयोग के आधार पर विभिन्न इकाइयों के साथ सामान्य सुविधाओं में हिस्सेदारी करता था जिससे उत्पादन की इकाई लागत में कमी हुई थी और उसके पास स्वयं की जेटी थी जो द्वीप से ही पोतों में संबद्ध वस्तु के सीधे लदान के लिए सक्षम थी। अतः, एसईपीएल को बड़े पैमाने पर किफायत, खरीद एवं संभार तंत्र, पाइपलाइन एकीकरण, प्रक्रिया संबंधी अवसंरचना और प्रौद्योगिकी का तुलनात्मक लाभ प्राप्त है और वह भिन्न-भिन्न मूल सामग्रियों/कच्ची सामग्रियों का भी प्रयोग करता है। घरेलू उद्योग ने एसईपीएल पर मुख्य मुद्दे अर्थात् यह कि आज की तारीख तक रिकॉर्ड में एससीएसएल का कोई उत्तर नहीं था और वे एससीएसएल को प्राप्त लाभों, यदि कोई हों, को एसईपीएल को प्राप्त लाभ नहीं बता सकते थे, से प्राधिकारी का ध्यान हटाने के लिए उन्हें भ्रमित करने के उद्देश्य से जान-बूझकर एसईपीएल और एससीएसएल का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर करने का आरोप लगाया है। किसी भी स्थिति में ये लाभ उनकी उत्पादन लागत में पूरी तरह प्रदर्शित होंगे। एसईपीएल ने प्रकटन के बाद इन आरोपों का खण्डन किया है।

**ड.) प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में**

15. घरेलू उद्योग ने माना है कि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में,

(i) एसईपीएल ने कहा है कि एसएसपी के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री प्रोपीलीन ऑक्साइड (पीओ) एससीएसएल और शेल सेरायस पायोनियर पीटीई लि० (एसएसपीएल) से प्राप्त किया जाता है, दोनों ही 100% सहायक कम्पनियाँ हैं, इसके अतिरिक्त अलग विधिक निकाय होने के बावजूद एससीएसएल को पूर्णतः एकीकृत लागत केन्द्र माना गया है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इसका तात्पर्य यह है कि संबद्ध वस्तु की लागत के निर्धारणार्थ दूर से क्रय कीमत या बाजार कीमत के स्थान पर एससीएसएल से खरीदे गए पीओ की कीमत उसकी लागत पर ली गई है; यही स्थिति संबंधित कम्पनी से खरीदे गए इथिलीन ऑक्साइड के मामले में भी है। एडी कानूनों में “व्यापार की सामान्य प्रक्रिया” जाँच के लिए अन्य कानूनी निकाय की लागतों को लिए जाने का प्रावधान नहीं है।

(ii) एसईपीएल ने संबंधित आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई निविष्टियों के कीमत निर्धारण का आधार और (क) ऐसी कीमतों से उचित बाजार कीमतों के प्रदर्शित होने; (ख) समान या तुलनीय निविष्टि के लिए स्वतंत्र पक्षकारों की क्रय कीमत के साक्ष्य संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

(iii) एसईपीएल ने वित्तीय/संविदाकारी श्रृंखलाओं तथा उत्पाद के लिए अन्य कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम, क्रय कीमत, निवेश को प्रभावित करने वाली वस्तुओं के संबंध में व्यापार व्यवस्था, वित्तीय लेखांकन प्रणाली एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखांकन पद्धतियों में परिवर्तन, उत्पादन उपकरणों के उपयोग की समय-सीमा, कीमत ह्रास, लागत केन्द्र, आदि के ब्यौरे बिना किसी कारण गुप्त रखे हैं। इसके अतिरिक्त, एसईपीएल ने उत्पाद कोडिंग प्रणाली, कीमतों में किसी अन्य विचार/संबंध/प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति आदि को शामिल करने, उत्पाद पर प्रभारित ब्याज लागतें, बिक्री किए गए सह-उत्पादों को लेखांकित करने, घरेलू एवं निर्यात बाजारों के लिए फैक्टरी लागत में अंतर के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(iv) आबद्ध या क्रीत निविष्टियों के संबंध में एसईपीएल ने प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए अपनी निविष्टियों के ब्यौरों के स्थान पर एससीएसएल में उत्पादित तथा एसएसपीएल से प्राप्त पीओ का उल्लेख किया था।

(v) एसईपीएल तथा बीएसईए ने जाँच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों में कम्पनी की संरचना में परिवर्तन संबंधी पूछताछ का उत्तर नहीं दिया है और न ही संबद्ध वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न संबंधित कम्पनियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं।

(vi) बीएसईए ने निर्यातक एवं सेराया के बीच के कर संबंधी करार, सम्पर्क व्यक्तियों के नाम, निविष्टियों की आपूर्ति करने वाली संबंधित कम्पनियों के ब्यौरे एवं उनके साथ संबंध की प्रकृति, कैटलॉग एवं पुस्तिकाएँ, फ्लो डायग्राम, चार्ट, वित्तीय एवं लागत लेखांकन प्रणाली तथा पिछले तीन वर्षों में

लैखांकन पद्धति में परिवर्तन, उत्पादन उपकरणों के प्रयोग की समय-सीमा, कीमत ह्रास, स्टॉक मूल्यांकन आदि को गोपनीय रखा है।

(vii) निर्यातक प्रश्नावली में बीएसईए ने प्रायः एससीएसएल के उत्तर का संदर्भ दिया है जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया जाना है।

(viii) बीएसईए ने करदाता ग्राहक के रूप में अपनी अक्षमता दर्शाते हुए क्रीत निविष्टियों पर करों/शुल्कों के भुगतान, निविष्टियों पर व्यय की गई परिवहन लागत, आबद्ध एवं संबंधित पक्षों से क्रीत कच्ची सामग्री के कीमत निर्धारण के आधार को स्पष्ट नहीं किया है और न ही उसने जाँच अवधि तथा पिछले वर्षों के लिए व्यापार, लाभ एवं हानि खाते, तुलन पत्र की प्रतियाँ प्रस्तुत की हैं।

(xi) बीएसईए के प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट-3 से भारत को कीमतों की तुलना में घरेलू बाजार तथा अन्य देशों में एफएसपी की उच्चतर कीमत प्रदर्शित होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि जाँच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन किया गया है और शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहेगा।

16. प्राधिकारी ने इन अभ्यावेदनों को नोट किया है और बीएसईए से संबंधित पूछताछ पर उनके उत्तरों का संज्ञान करते हुए इस जाँच परिणाम में उचित स्थानों पर उन अभ्यावेदनों की जाँच की है।

#### च) अनुसंधान एवं विकास व्ययों के संबंध में

17. एसईपीएल ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग के कुल कारोबार की तुलना में अनुसंधान एवं विकास पर उनका व्यय केवल 0.18% था जो कि वर्ष 2005-06 के लिए उनकी वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है और वे बेहतर प्रौद्योगिकी, अवसंरचना आदि में निवेश करके प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का प्रयास करने के बजाय विदेशी प्रतिस्पर्धियों पर लगाए जा रहे पाटनरोधी शुल्क की सुरक्षा का सहारा ले रहे थे। घरेलू उद्योग ने कहा है कि किसी पाटनरोधी जाँच में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय का स्तर असंगत था और अपने कथन की संगतता को सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ सामग्री प्रस्तुत किए बिना केवल एक वक्तव्य दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एफएसपी के विनिर्माण हेतु घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी विश्व के किसी भी अन्य उत्पादक की प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है।



**च. पाटन का जारी रहना**

18. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 क (क) (ग) के अंतर्गत

"किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) व्यापार की साधारण प्रक्रिया में समान वस्तु हेतु तुलनीय कीमत जब यह निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र में उपभोग के लिए हो जैसा कि उप-नियम (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है; अथवा

(ii) जब व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कोई बिक्रियां न हों अथवा जब निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्रियों की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियां एक उचित तुलना की अनुमति न दें, तो सामान्य मूल्य या तो

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत जब इसे निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात किया गया हो जैसा कि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है; या

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित, प्रशासनिक बिक्री एवं सामान्य लागतों तथा लाभ हेतु तर्कसंगत वृद्धि के साथ उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते कि उद्गम के देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां वस्तु का निर्यात किया गया है या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।"

19. प्राधिकारी ने धारा 9 क (1) (क) के अनुसार सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं। सिंगापुर से केवल दो निर्यातकों ने प्रत्युत्तर दिया था।

**च.1. ई यू जापान सिंगापुर और यू एस ए हेतु सामान्य मूल्य का निर्धारण****च.1.1 हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

20. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में उत्पाद की घरेलू बाजार कीमतों के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण या विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने की असमर्थता और सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी सूचना की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय (एस जी ए) और तर्कसंगत लाभ सहित भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। उन्होंने दावा किया है कि उन स्रोतों से पाटन बंद नहीं हुआ है जिन पर शुरुआत में पाटनरोधी शुल्क

लगाए गए थे और यदि शुल्कों को वापस लिया जाता है तो पाटन का प्रभाव और अधिक गंभीर होगा । संबद्ध देशों के निर्यातक पी ओ आई से पहले के वर्षों में उनके कीमत व्यवहार में बगैर किसी परिवर्तन के पाटन में शामिल रहे थे और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे ।

21. एस ई पी एल ने यह बताते हुए पाटन के आरोप का खंडन किया है कि इसने संबद्ध उत्पाद की बड़ी मात्रा का एशिया प्रशांत एवं भारत सहित अन्य क्षेत्रों को निर्यात किया है और घरेलू बाजार में भी इसकी बिक्री की है; कि कम कीमतों पर आयातों से अपने आप में पाटन का संकेत नहीं मिलता है; कि उनके प्रश्नावली उत्तर से यह साबित हुआ कि एस सी एस एल के विश्वस्तरीय संयंत्र जिसमें श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी है और घरेलू उद्योग की तुलना में सात गुना अधिक घोषित क्षमता के साथ उच्च पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हैं, के कारण एफ एस पी उत्पादन लागत 2174 पी एम टी अम.डालर के कथित परिकलित मूल्य से अत्यधिक कम थी; कि प्राधिकारी को उनके आंकड़ों का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए और घरेलू बिक्री कीमत एवं विनिर्माण लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य की संगणना करनी चाहिए, न कि परिकलित सामान्य मूल्य की ।

22. इसी तरह बी एस ई ए ने दावा किया है कि भारत को उनकी औसत सी आई एफ कीमत पी ओ आई के दौरान आई सी आई एस कीमत और घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल याचिका में बतायी गयी औसत सी आई एफ कीमत से अधिक थी और पाटन मार्जिन निकालने के लिए निर्यात कीमत की निर्यातक की घरेलू कीमतों के साथ तुलना करनी थी, न कि अन्यत्र बतायी गई कीमतों के साथ । इसके अलावा, सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले विनिर्माता का उत्तर प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था लेकिन एस सी एस एल (जिसे बी एस ई ए हेतु एफ एस पी का उत्पादक बताया गया है) से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में निर्यातक के सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता बल्कि इसका परिकलन करना होगा ।

23. बी एस ई ए ने यह भी बताया है कि संबद्ध वस्तु हेतु पहुँच मूल्य निर्धारित संदर्भ कीमत से अधिक था और इस बात पर विचार करते हुए कि निर्यातकों ने अपनी दलील के समर्थन में एक ई सी प्रकरण संलग्न करने से पहले काफी अधिक उच्च कीमतें बनाये रखी हैं, यदि मौजूदा उपायों को वापस लिया जाता है तो इस बात की कोई वजह नहीं है कि निर्यातक निम्न कीमतें लागू करेंगे । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि कच्चे माल की कीमतों में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी के कारण संबद्ध वस्तुओं के पहुँच मूल्य में वृद्धि हुई है और तब भी यह कुल लागत में हुई बढ़ोतरी से कम थी और आयात अब भी पाटित कीमतों पर आ रहे हैं । इसके अलावा, ई सी प्रकरण के तथ्य भिन्न थे और वह तुलना सही नहीं थी ।

24. डी पी एफ ने निवेदन किया है कि यह मानने के लिए कोई आधार नहीं था कि जब पी ओ आई के दौरान आयातों के पहुँच मूल्य और संदर्भ कीमत के बीच अत्यधिक अंतर था, निर्यातकों के कीमत व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है । यदि घरेलू उद्योग के आरोप सत्य थे तो निर्यातक यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हो, वे संदर्भ कीमत या इससे कम पर निर्यात कर रहे होंगे और स्पष्ट रूप से यह बात नहीं थी । डी पी एफ ने यह भी निवेदन किया है कि यदि संबद्ध देशों के निर्यातक निर्णायक समीक्षा जाँच में सहयोग नहीं करते और प्राधिकारी सर्वोत्तम निर्णय आकलन के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज करते हैं तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के एकाधिकार स्वरूप के कारण निर्यातक देश में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत की कम कीमत, तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत और परिकलित सामान्य मूल्य अपनाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने इस निवेदन को यह

कहते हुए अस्वीकार किया है कि सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ ऐसा दृष्टिकोण अपनाने का कानूनी औचित्य नहीं दिया गया है।

25. आयातक ने यह भी कहा है कि पी ओ आई के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग लगभग 30,000 मी.टन थी जिसमें प्रति वर्ष लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। यद्यपि घरेलू उद्योग की लाइसेंसशुदा क्षमता 37,000 मी.टन थी, तथापि इसकी स्थापित क्षमता 14,000 मी.टन थी जिसमें इसने अन्य पोलियोल का भी उत्पादन किया था। अतः इसके पास मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं थी और 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर भी यह 50 प्रतिशत मांग को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग देश में लघु उद्योग (एस एस आई) अपने एकाधिकारी दर्जे की कीमत पर अनुचित लाभ कमाने के लिए, जो संबद्ध वस्तु के अंतिम प्रयोक्ता हैं, और रक्षोपाय एवं पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग करने की मांग करते हुए मांग में बढ़ोतरी के अनुपात में अपनी क्षमता में बढ़ोतरी करने में विफल रहा है। अतः मांग में कमी आयातों से पूरी करनी होगी। यदि उच्च पाटन मार्जिन के कारण पाटनरोधी शुल्क बहुत अधिक है तो उन लघु उद्योगों को गंभीर क्षति पहुँचेगी जो संबद्ध वस्तु का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं।

26. घरेलू उद्योग ने उत्तर दिया है कि यदि उनके उत्पादों हेतु एक तर्कसंगत बिक्री कीमत का आश्वासन दिया जाए तो उनके पोलियोल संयंत्र की 15500 मी.टन की वर्तमान क्षमता को प्रक्रिया आशोधनों के द्वारा बढ़ाकर 23000 मी टन प्रति वर्ष किया जा सकता है। इस समय वे वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस बात का सुझाव देने का कोई विधिक कारण नहीं था कि यदि घरेलू उद्योग देश में समूची मांग की पूर्ति नहीं कर सकता है तो पाटनरोधी शुल्कों को लागू नहीं किया जा सकता है। संबद्ध देशों से एफ एस पी के आयातों में अत्यधिक पाटन के कारण बढ़ोतरी हुई है न कि घरेलू मांग में बढ़ोतरी के कारण। यदि आयात गैर-पाटित आयातों पर होते तो उद्योग को भी संबद्ध वस्तु की उचित कीमत प्राप्त हुई होती।

## च.2 प्राधिकारी द्वारा जाँच

27. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों एवं प्रति-तर्कों को नोट किया है और मुद्दों का जाँच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर समाधान किया गया है।

सी टी अधिनियम की धारा 9 क (5) में प्रावधान है कि किसी निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या ऐसे शुल्क को बंद कर देने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। अतः प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए निम्न मुद्दे हैं

- यदि निश्चयात्मक शुल्कों को हटाया जाता है या खत्म किया जाता है तो क्या पाटन के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है;
- यदि निश्चयात्मक शुल्कों को खत्म किया जाता है या इन्हें हटाया जाता है तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

इन मुद्दों की आगामी पैराग्राफों में जांच की गई है।

### च.2.1 सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत

28. प्राधिकारी ने नोट किया कि सिंगापुर से एस ई पी.एल और बी एस ई ए के सिवाय संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के निर्धारणार्थ सूचना उपलब्ध नहीं करायी है अथवा जांच में सहयोग नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से असहयोगी निर्यातकों हेतु पाटन मार्जिन का निर्धारण करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। इस जांच के प्रयोजनार्थ पी ओ आई हेतु अपनायी गई औसत विनिमय दर 44.62 रुपए प्रति डालर थी।

#### च.2.1.1 अमरीका हेतु सामान्य मूल्य

29. प्राधिकारी ने तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ भारत में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, परिवर्तन लागतों एवं बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। इस तरह परिकलित सामान्य मूल्य \*\*\* रुपए/या \*\*\* डा. प्रति मी.टन है।

#### च.2.1.2 जापान हेतु सामान्य मूल्य

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डी जी सी आई एस से सौदेवार आंकड़ों के अनुसार पी ओ आई और आयात वर्ष में जापान से कोई आयात नहीं किए गए थे जबकि अंतरिम वर्षों में आयात निर्धारित न्यूनतम सीमा पर थे। अतः जापान के लिए किसी पाटन मार्जिन की गणना नहीं की गई है।

#### ड.2.1.3 यूरोपीय संघ हेतु सामान्य मूल्य

21. प्राधिकारी ने तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ भारत में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, परिवर्तन लागतों एवं बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। परिकलित सामान्य मूल्य \*\*\* रुपए या \*\*\* डा. प्रति मी.टन है।

#### च.2.1.4 सिंगापुर हेतु सामान्य मूल्य

32. इस जांच में सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का नियमों के अनुसार सत्यापन किया गया था और प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे सत्यापन की रिपोर्टें निर्यातकों को उनकी टिप्पणियों हेतु उपलब्ध कराई गई थी। इन निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन का परिकलन सत्यापन रिपोर्टों पर निर्यातकों की टिप्पणियों को प्रासंगिक एवं वैध सीमा तक ध्यान में रख कर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिविल अपील सं० वर्ष 2001 की 1294, मै० आर आई एल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि सामान्य मूल्य उत्पादक-विशिष्ट नहीं होता है बल्कि निर्यातक देश विशिष्ट होता है।

34. प्रकटन के बाद की अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग में यह अनुरोध किया है कि एकल भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना सहयोगी निर्यातकों के लिए नहीं है और ऐसे प्रत्येक निर्यातक के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है, जो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में बिक्री की अलग-अलग स्थितियाँ होने के कारण निर्यातक देश में भारित औसत सामान्य मूल्य से अत्यधिक विकृत परिणाम प्राप्त होता है। तथापि उपर्युक्त मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में संबद्ध देशों हेतु संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्यों का प्रथमतः अलग-अलग सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारण किया गया है और तब सहयोगी निर्यातकों हेतु निर्धारित सामान्य मूल्यों के आधार पर निर्यातक देश हेतु विचाराधीन उत्पाद के लिए एकल भारित औसत सामान्य मूल्य का परिकलन समग्र रूप से किया गया है।

निर्यातक सत्यापन की मुख्य-मुख्य विशेषताएं

(क) एस ई पी एल

35. एस ई पी एल सिंगापुर में निगमित एवं पंजीकृत एक प्राइवेट लि० कम्पनी है और संबद्ध उत्पाद एवं अन्य उत्पादों की एक विनिर्माता है। एस ई पी एल के एफ एस पी संयंत्र सिंगापुर में अवस्थित हैं और इनका प्रचालन एफ सी एस एल, जो एस ई पी एल की उत्पादन सुविधा है जिसे प्रारंभ में शैल एवं मित्सुबिशी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 100 प्रतिशत सहायक कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, द्वारा किया जाता है। यद्यपि यह एक पृथक विधिक सत्ता है तथापि इसे सांविधिक लेखों के भीतर पूर्ण रूप से एकीकृत लागत केन्द्र और एस ई पी एल के साथ एक एकल सत्ता माना जाता है। यह एक विनिर्माण लागत केन्द्र है जो अन्य वस्तुओं के साथ-साथ पी ओ का उत्पादन करता है जिसका पूरा हिस्सा एस ई पी एल को लागत पर बेचा जाता है और इसका एफ एस पी और अन्य उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। पी ओ हेतु घोषित क्षमताएं \*\*\* हे० और एफएस पी हेतु \*\*\* प्रति वर्ष है।

36. एस एस पी एल वर्ष 2002 में स्थापित एस ई पी एल की एक अन्य 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है जो मुख्यतः पी ओ की बिक्री में लगी हुई है। यह एक पृथक विधिक सत्ता है और अन्य ग्राहकों को पी ओ की बिक्री करती है। इसके अलावा, बी ए एस एफ के साथ 50 प्रतिशत भागीदारी में, एस एस पी एल ने ई एल एल बी ए नामक एक अन्य पृथक विधिक सत्ता का गठन कर दिया है जिसका पी ओ वार्षिक उत्पादन \*\*\* है। ई एल एल बी ए को एक लागत केन्द्र माना जाता है और इसका मुख्य कार्यकलाप पी ओ का उत्पादन और इसके शेषधारकों को लागत पर इसकी बिक्री करना है।

37. एस ई पी एल विभिन्न स्रोतों से प्रोपीलीन फीड-स्टाक की खरीद करता है और इसे प्रोपीलीन आक्साइड में परिवर्तित करके इसका आयात करता है, पी ओ आई में क्रय कीमत \*\*\* अम.डालर \*\*\* पी एम टी के बीच थी। उपभोग की जाने वाली पी ओ एस सी एस एल एस एफ पी एल और बी एस ई ए से आती है, मुख्य आपूर्ति एस सी एस एल और एस एस पी एल से आती है और टाप-अप आपूर्ति बी एस ई ए से आती है। एस ई पी एल की बी एस ई ए के साथ टोलिंग व्यवस्था है जिसमें बी एस ई ए से प्राप्त पी ओ को पोलियोल में परिवर्तित किया जाता है और इसके ई एल एल बी ए संयंत्र से बी एस ई ए को वापस आपूर्ति की जाती है। अतः पी ओ

की भारत औसत कीमत को उत्पादन लागत पर प्रभारित किया गया है। अपने विभिन्न अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने यह दोहराया है कि पीओ को बाजार कीमतों पर लिया जाना चाहिए और न कि लागत पर। चूँकि एससीएसएल, एसईपीएल का एक पूर्णतः समेकित लागत केन्द्र है इसलिए पीओ को बाजार कीमत पर प्रभारित करने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं है।

38. एफ एस पी का उत्पादन एस ई पी एल द्वारा पी ओ की प्रतिक्रिया और प्रारंभक के रूप में गलिसरीन के साथ ई ओ ग्रेड के आधार पर किया जाता है। प्रमुख कच्ची सामग्री पी ओ संबद्ध उत्पाद का भार के हिसाब से लगभग 90 प्रतिशत है, ई ओ गलिसरीन संयुक्त रूप से भार का लगभग 10 प्रतिशत है। ई ओ की आपूर्ति इथीलिन ग्लाइकोल सिंगापुर (ई जी एस) जो एस ई पी एल का एक संयुक्त उद्यम है, द्वारा पाइपलाइन के द्वारा की जाती है जबकि गलिसरीन की आपूर्ति न्यूनतम संभार तंत्र संबंधी लागत के साथ मलेशिया से बल्क खेपों में की जाती है। एस ई पी एल पोलियोल के तीन अन्य ग्रेडों का उत्पादन भी करता है यद्यपि मुख्य उत्पादन संबद्ध उत्पाद का होता है जो अन्य के साथ घरेलू एवं भारत सहित निर्यात बाजारों में बेचा जाता है। उत्पादन लागत का सत्यापन \*\*\* अम.डालर के रूप में किया गया था।

39. घरेलू बाजार में पोलियोल एस सी 56 - 02 की बिक्रियों के सौदेवार व्यौरों से पता चला कि ये बिक्रियां \*\*\* मी.टन थी। बी एस ई ए को बिक्रियां जिन्हें घरेलू सौदों जो एक टोलिंग करार के अंतर्गत है, की परिधि से बाहर रखा गया था, पी ओ आई के दौरान \*\*\* मी.टन थी। बिक्रियां भिन्न-भिन्न कीमतों पर रही हैं। बेयर जो न तो एक सहायक कंपनी थी और न ही एक संबद्ध कंपनी थी, को बिक्रियां तुलनात्मक रूप से बड़े क्रेता के रूप में तुलनात्मक रूप से कम दरों पर रही हैं। अन्य ग्राहकों के लिए प्रभारित कीमत बाजार पर आधारित थी। कंपनी की सभी घरेलू बिक्रियां उत्पादन लागत एवं इन सौदों की औसत बिक्री कीमत से अधिक थीं और ये \*\*\* अम.डालर/मी.टन बनती हैं। अंतर्देशीय भाड़े, भंडारण, राष्ट्रीय ऋण लागत, सर्वेक्षक और मूरिंग शुल्कों के लिए घरेलू बिक्रियों पर समायोजनों की सत्यापन के पश्चात अनुमति दी गई है। समायोजनों का निवल भारत औसत कारखाना द्वार सामान्य मूल्य \*\*\* अम.डालर प्रति मी.टन बनता है।

घरेलू बिक्रियां	इकाई बिक्री कीमत	समायोजन	कारखाना द्वार सामान्य मूल्य
मी.टन में	डालर/मी.टन	डालर/मी.टन	डालर/मी.टन
***	***	***	***

#### (ख) बी एस ई ए

40. बी एस ई ए, बी ए एस एफ समूह कंपनियों का एक भाग है और इसका वैश्विक मुख्यालय ब्रुसेल्स में है जो क्षेत्रीय व्यावसायिक इकाइयों, लुडविशाफेन में एक वैश्विक आर एंड डी, हांगकांग में एशियाई क्षेत्र विपणन एवं प्रौद्योगिकी मुख्यालय और प्रत्येक देश में स्थानीय बिक्री कार्यालयों में समन्वय करता है। लागत बंटवारे संबंधी व्यवस्थाओं की देख-रेख वैश्विक सत्ताओं द्वारा की जाती है। एक विनिर्माण कंपनी के रूप में बी एस ई ए वित्त एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कार्यों की देखरेख करता है।

41. बी एस ई ए के पास अपनी एफ एस पी विनिर्माण सुविधा नहीं थी। प्रोपीलीन की खरीद ई ए एल बी ए जो शैल एवं बी ए एस एफ का एक 50 - 50 संयुक्त उद्यम है, द्वारा की जाती है और पी ओ में परिवर्तित किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं का बी ए एस एफ के साथ कोई कानूनी संबंध नहीं था और प्रोपीलीन की खरीद आंशिक रूप से मौके के आधार पर प्रचलित बाजार स्थितियों पर स्थानीय एवं विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की जाती है। बी एस ई ए ने एस सी एस एल के साथ एक टोलिंग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए थे जो वर्ष 2002 से प्रभावी है जिसमें बी एस ई ए, एस सी एस एल को पी ओ की आपूर्ति करेगा जो एफ एस पी का उत्पादन करेगा और इसे बी एस ई ए को वापस भेजेगा। बी एस ई ए वार्षिक मात्रा के अंतिम प्लेटों पर पहुँचने तक टोलिंग शुल्क के अध्यधीन एफ एस पी की बढ़ती हुई मात्रा का सोर्स कर सकता था जिसमें सभी वास्तविक लागत एवं आय की एक उपयुक्त दर शामिल है। यह व्यवस्था प्रथम एफ एस पी आपूर्ति की शुरुआत के 7 वर्ष बाद समाप्त की जा सकती है। बी एस ई ए इस तैयार उत्पाद की बिक्री अपनी विपणन व्यवस्था और एक भिन्न ब्रांड नाम के अंतर्गत करता है। एस ई पी एल और बी एस ई ए दो पृथक विधिक सत्ताएं हैं और इनमें इस व्यवस्था के सिवाय कुछ भी साझा नहीं है।

42. घरेलू बिक्रियों के विश्लेषण से प्रदर्शित हुआ कि बी एस ई ए ने \*\*\* मी.टन की बिक्री सिंगापुर में लाभ पर की थी और पी ओ आई के दौरान भारत को \*\*\* मी.टन का निर्यात किया था। घरेलू बिक्रियां भारत को उनके निर्यातों का लगभग \*\*% हिस्सा है। बी एस ई ए ने वेयरहाउसिंग कंपनी की सेवाओं का उपयोग किया था और उनकी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया था।

43. अतः बी एस ई ए की उत्पादन लागत पी ओ की लागत, पी ओ को एफ एस पी में परिवर्तित करने हेतु टोलिंग शुल्क, परिवर्तनीय एवं निर्धारित विनिर्माण संबंधी ऊपरी खर्च, निवेश पर आय और नौ-परिवहन की लागत को प्रदर्शित करती है। एस जी ए व्ययों, जिनमें हांगकांग स्थित उनके विपणन कार्यालयों और ब्रुसेल्स स्थित प्रशासनिक कार्यालय का प्रतिशत हिस्सा शामिल था, को जोड़ दिया गया था। अंतर्देशीय मालभाड़े, पैकिंग लागत एवं उठाई शुल्क को समायोजित करने के पश्चात कारखाना द्वार सामान्य मूल्य निम्नानुसार है:-

घरेलू बिक्रियां	इकाई बिक्री कीमत	समायोजन	कारखाना द्वार सामान्य मूल्य
मी.टन में	डालर/मी.टन	डालर/मी.टन	डालर/मी.टन
***	***	***	***

44. सी ए सं0 1294/2001 में उच्चतम न्यायालय के आदेश कि सामान्य मूल्य निर्यातक देश-विशिष्ट होता है, के अनुसरण में सिंगापुर के लिए संबद्ध उत्पाद हेतु एकल भारित औसत सामान्य मूल्य का सहयोगी निर्यातकों के सामान्य मूल्यों के आधार पर समग्र रूप से परिकलन किया गया है। निर्यातकों के अलग-अलग पाटन मार्जिन का निधारण करने के लिए सामान्य मूल्य की तुलना अलग-अलग निर्यातकों हेतु निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य \*\*\* डालर या \*\*\* रूपए प्रति मी.टन है।

	एस ई पी एल	बी एस ई ए	भारित औसत
सामान्य मूल्य	***	***	***

## पाटन मार्जिन का परिकलन करने की विधि

### च.3 निर्यात कीमत

45. संबद्ध देशों से असहयोगी निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन एवं कीमत कटौती की गणना करने के लिए अधिकारिक कीमत को लिया है। संबद्ध उत्पाद के लिए भारत को भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। मालभाड़े, बीमा, कमीशन एवं हैंडलिंग व्ययों जैसे समायोजनों की परम्परागत रूप से अनुमति दी गई है। प्रकटन के बाद की अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि असहयोगी निर्यातकों के लिए प्राधिकारी को न्यूनतम निर्यात कीमत और न की भारित औसत निर्यात कीमत लेनी चाहिए। तथापि, असहयोगी देशों के लिए प्राधिकारी ने सौदों के शुन्चीकरण का परिहार करने के लिए निरंतर अपनाई जाने वाली पद्धति, भारित औसत निर्यात कीमत को अपनाया है।

#### च.3.1 यू एस ए हेतु निर्यात कीमत

46. भारित औसत निर्यात कीमत \*\*\* अम.डालर प्रति मी.टन के रूप में ली गई है और समायोजनों के बाद कारखाना द्वार निर्यात कीमत \*\*\* डालर प्रति मी.टन बनती है।

#### च.2.2 यूरोपीय संघ हेतु निर्यात कीमत

47. भारित औसत निर्यात कीमत \*\*\* अम.डालर प्रति मी.टन के रूप में ली गई है और समायोजनों के बाद कारखाना द्वार निर्यात कीमत \*\*\* डालर प्रति मी.टन बनती है।

#### च.2.3 सिंगापुर हेतु निर्यात कीमत

48. प्राधिकारी ने सिंगापुर से सहयोगी निर्यातकों की निर्यात बिक्रियों संबंधी आंकड़ों का सत्यापन किया था और निर्यात कीमत का निम्नानुसार निर्धारण किया है:

#### क. एस ई पी एल

49. एस ई पी एल ने पी ओ आई में कई देशों को एफ एस पी का निर्यात किया था। पी ओ आई में तीसरे देश के निर्यात (भारत को छोड़कर)\*\*\* मी.टन थे जबकि भारत को निर्यात \*\*\* मी.टन या कुल निर्यातों का 3.3 प्रतिशत था। \*\*\* मी.टन का सड़क/समुद्र के जरिए बल्क कंटेनरों द्वारा \*\*\* मी.टन का बल्क टैंकरों और \*\*\* मी.टन का सड़क एवं समुद्र के जरिए पैकड कंटेनरों द्वारा निर्यात किया गया था। परिवहन की विभिन्न पद्धतियों, रिबेट/कमीशन, राष्ट्रीय ऋण लागत, अंतर्देशीय क्रास पत्तन, आउटबाउन्ड एवं विदेशी मालभाड़ा, लदान, बीमा, पत्तन, भंडारण एवं नाइट्रोजन इन्वर्टिंग, सवेक्षण एवं मूरिंग शुल्क एवं पैकिंग लागतों के अनुसार समायोजनों की जांच की गई थी। विभिन्न पद्धतियों हेतु प्रति इकाई कारखाना द्वार निर्यात कीमत की गणना की गई थी और समायोजन के बाद कारखाना द्वार स्तर पर भारित औसत निर्यात कीमत \*\*\* अम.डालर प्रति मी.टन बनती है।



विवरण	डालर/मी. टन
निर्यात कीमत	**
कम समायोजन	***
कारखाना द्वार निर्यात कीमत	***

### ख. बी एस ई ए

50. संबद्ध वस्तु में बी एस ई ए एक व्यापारी होने के कारण पैकिंग प्रभार, उठाई शुल्क, मालभाड़े के लिए इकाई निर्यात कीमत का समायोजन किया गया था और प्रति इकाई कारखाना द्वार कीमत अंतर्देशीय परिवहन की गणना नीचे दी गई है:-

विवरण	डालर/मी. टन
निर्यात कीमत	**
कम समायोजन	***
कारखाना द्वार निर्यात कीमत	***

### ग. सिंगापुर से अन्य निर्यातक

51. अन्य निर्यातकों के लिए विधिवत रूप से समायोजित एस ई पी एल को न्यूनतम निर्यात कीमत कारखाना द्वार निर्यात कीमत के रूप में ली गई थी।

### च.4 पाटन मार्जिन

#### च.4.1 यू एस ए हेतु पाटन मार्जिन

52. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का परिकलन परिकलित सामान्य मूल्य एवं उत्पाद हेतु निर्धारित निर्यात कीमत के आधार पर कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य एवं भारित औसत निर्यात कीमतों के बीच तुलना करके किया है। पाटन मार्जिन \*\*\* डालर प्रति मी. टन या 18.96 प्रतिशत है जो अत्यधिक है।

#### च.4.2 यूरोपीय संघ हेतु पाटन मार्जिन

53. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का परिकलन परिकलित सामान्य मूल्य एवं उत्पाद हेतु निर्धारित निर्यात कीमत के आधार पर कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य एवं भारित औसत निर्यात कीमतों के बीच तुलना करके किया है। पाटन मार्जिन \*\*\* डालर प्रति मी. टन या 0.40 प्रतिशत है।

**च. 4.3 सिंगापुर हेतु पाटन मार्जिन**

54. प्राधिकारी ने भारित औसत सामान्य मूल्य एवं कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के बीच तुलना करके पाटन मार्जिन की गणना की है। सहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक है। प्राधिकारी ने नोट किया कि न्यायालय के इस निर्णय, कि सामान्य मूल्य निर्यातक देश विशिष्ट होना चाहिए न कि निर्यातक विशिष्ट, के परिणामस्वरूप बीएसईए का पाटन मार्जिन नकारात्मक है। अन्य के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण भारित औसत सामान्य मूल्य तथा समायोजन के बाद सहयोगी निर्यातकों की न्यूनतम निर्यात कीमत के बीच के अन्तर के रूप में किया गया है। इस प्रकार पाटन मार्जिन \*\*\*\* डॉलर प्रति मी. टन अथवा 0.45% है।

**च.5 पाटन मार्जिन: सारांश**

उत्पाद	देश	निर्यातक	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
			डॉलर पीएमटी	
फ्लेक्सिबल स्टेवस्टॉक पोलिबोल ऑफ एमडब्ल्यू 3000-4000	यूएसए	सभी	***	18.96%
	जापान		जाँच अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं	
	सिंगापुर	एसईपीएल	***	-5.39%
		बीएसईए	***	-6.19%
		अन्य	***	0.45%
	ईयू	सभी	***	0.40%

अमरीका और ईयू से संबद्ध उत्पाद के आयातों के मामलों में निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक और निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

55. अमरीका से पाटन मार्जिन अत्यधिक है। जाँच अवधि के दौरान सिंगापुर या ईयू से पाटन मार्जिन ऋणात्मक या मामूली पाया गया था। जाँच अवधि के दौरान जापान से कोई निर्यात नहीं हुआ था और इसलिए, इस देश के लिए वर्तमान पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सका। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी निर्णायक समीक्षा में वर्तमान पाटन मार्जिन वास्तविक तथ्य नहीं होता है बल्कि जाँच अवधि के दौरान कोई पाटन नहीं होने की स्थिति में उसके पुनः प्रारंभ होने की संभावना की जाँच किया जाना अपेक्षित होता है।

**छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध : क्षति की निरंतरता**

56. पाटनरोधी नियमावली का नियम 11 निम्नानुसार है :

क्षति का निर्धारण :

(1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी जाँच परिणाम में दर्ज करेंगे कि ऐसी वस्तु का भारत में आयात किसी स्थापित उद्योग को क्षति पहुँचाता है अथवा पहुँचने की जोखिम रखता है अथवा भारत में स्थापित किसी उद्योग को अवरुद्ध करता है।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जोखिम, घरेलू उद्योग के संगठन को हुई वास्तविक बाधा तथा पाटित आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण करेंगे, जो पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु पर उनकी कीमत के प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के प्रभाव तथा इस नियमावली के अनुबंध II में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसरण में..... किया जाएगा।

57. नियमावली के अनुबंध II में अपेक्षा की गई है कि क्षति के निर्धारण में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जाँच निहित होगी (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान प्रकार की वस्तु के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) इस प्रकार के उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामस्वरूप प्रभाव। नियमावली के अनुबंध- II (ii) में निम्नलिखित प्रावधान है :-

(ii) पाटित आयातों की मात्रा की जाँच करते हुए उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में या तो निरपेक्ष रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में या तो निरपेक्ष रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचार करेंगे कि क्या भारत समान उत्पाद के मूल्यों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्यों में काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव, अन्यथा, मूल्यों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक कम करने के लिए है अथवा मूल्य में अन्यथा होने वाली महत्वपूर्ण वृद्धि को रोकने के लिए है।

नियमावली के अनुबंध II में आगे यह भी प्रावधान है कि

(iv) “घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करते समय उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों तथा संकेतकों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता का उपयोग में वास्तविक एवं संभावित कमी, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, सूचियों में वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता शामिल है।”

### छ.1. हितबद्ध पक्षों के विचार

58. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि निर्णायक समीक्षा में क्षति का विश्लेषण घरेलू उद्योग पर सम्भावित प्रभाव के विश्लेषण द्वारा किया जाना अपेक्षित है, यदि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाए गए हों। पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ था जो इस बात का द्योतक है कि शुल्क कारगर रहे

थे, परन्तु उनका प्रभाव वांछित स्तर तक नहीं हुआ क्योंकि निर्यातक क्षतिकारी पाटन में संलिप्त रहे हैं और यदि शुल्क नहीं बढ़ाए जाते, तो घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहेगा।

59. अन्य हितबद्ध पक्षों का यह तर्क है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ था और उसे अभी कोई क्षति नहीं है और क्षति, यदि कोई हो, उसकी स्वयं की अक्षमताओं के कारण है और इन स्रोतों से आयातों के कारण नहीं है। स्वयं याचिका के अनुसार अनेक क्षति सूचकांकों से सुधार अथवा मामूली गिरावट प्रदर्शित होती है, जिससे यह तात्कालिक निकष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटन के कारण नहीं हुई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि निर्णायक समीक्षा में पाटन तथा क्षति पर ध्यान केन्द्रित किया गया था, अतः यदि पाटन नहीं हुआ है तो “सम्भावना” के परीक्षण से इसका कोई संबंध नहीं है।

## छ.2. प्राधिकारी द्वारा जाँच

60. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा अपने निवेदनों में उठाए गए मुद्दों पर विचार किया है और पाटन जारी रहने तथा घरेलू उद्योग को क्षति की सम्भावना की जाँच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत तर्कों के आलोक में की गई है।

61. प्राधिकारी ने नोट किया कि यह पहले से ही लागू उपाय की निर्णायक समीक्षा है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संचयी आकलन के मुद्दे की जाँच पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (iii) के अनुसरण में सम्बद्ध देशों से एक साथ हुए पाटन के कारण की गई और उनका यह अभिमत है कि जापान से आयातों को छोड़कर इस मामले में संचयी आकलन के प्रयोजनार्थ उक्त नियमों में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं।

62. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सम्बद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमतों के घरेलू उद्योग पर हुए प्रभाव तथा इसकी कीमतों व लाभप्रदता पर हुए प्रभाव की जाँच की है। क्षति के अस्तित्व तथा पाटन एवं क्षति, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध की जाँच के लिए सम्बद्ध देशों से हुए निर्यातों के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित हुई है अतः क्षति के विश्लेषण एवं कारणात्मक संबंध की जाँच के प्रयोजनार्थ समस्त निर्यातों को पाटित आयात माना गया है।

## क. पाटित आयातों की मात्रा का प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर इनका प्रभाव

### आयात आँकड़े

63. डीजीसीआई एण्ड एस से प्राप्त सौदेवार आंकड़े दर्शाते हैं कि सम्बद्ध उत्पाद के आयात सीमाशुल्क वर्गीकरण 39072000, 39072010 तथा 39072090 के अंतर्गत सूचित किए गए हैं। चूँकि उत्पाद का विवरण केवल संकेतात्मक है अतः मात्रा, मूल्य तथा औसत आयात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध देशों के सभी आयातों को शामिल कर लिया गया है, चाहे उनका वर्गीकरण कुछ भी हो। चूँकि सिंगापुर के निर्यातकों ने भारत को किए गए निर्यातों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जिनकी मात्रा व मूल्य जांच अवधि के संबंध में डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों से अधिक हैं, अतः इन्हीं आंकड़ों को अपनाया गया है

और जाँच अवधि (पीओआई) से संबंधित कॉलम में दर्शाया गया है। अधिकांश उत्पाद का आयात इस समय सम्बद्ध देशों से हुआ है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

एफएसपी आयात	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि <sup>1</sup>	जाँच अवधि <sup>2</sup>
उत्पाद का कुल आयात					
मात्रा (मी. टन)	9531.36	10491.80	12992.14	13795.06	15249.18
मूल्य (लाख रु.)	4190.60	5514.14	9086.87	11377.88	12262.62
कीमत/मी. टन	43966	52557	69941	(82478)	80415
संबद्ध देशों से आयात					
मात्रा (मी. टन)	586.62	3258.96	6101.00	9622.13	11076.25
मूल्य (लाख रु.)	346.38	1845.03	4163.56	7945.08	8829.83
कीमत/मी. टन	59048	56614	68244	82571	79719
कुल आयातों में हिस्सा	6.15	31.06	46.96	(69.75)	72.64
अन्य देशों से आयात					
मात्रा (मी. टन)	8946.01	7232.84	6891.14	4172.93	
मूल्य (लाख रु.)	3844.78	3669.11	4923.31	3432.80	
कीमत/मी. टन	42978	50729	71444	82264	

टिप्पणी: जाँच अवधि<sup>1</sup>: डीजीसीआईएस के आंकड़े; जाँच अवधि<sup>2</sup>: निर्यातकों के आंकड़े.

64. प्राधिकारी ने नोट किया कि वर्ष 2002-03 में उत्पाद के मात्र 6% कुल आयात के बाद परवर्ती वर्षों के दौरान सम्बद्ध देशों से आयात बढ़कर क्रमशः 31%, 47% एवं 73% हो गए, जिनमें अत्यधिक तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। वर्तमान जाँच के दायरे में जो देश शामिल नहीं हैं अर्थात् ब्राजील, कोरिया, चीन जन. गण. तथा चीनी ताइपेई से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। जो देश पाटन नहीं कर रहे हैं, उन सहित कुल आयातों में इनका हिस्सा 2002-03 के दौरान 94% था और जाँच अवधि के दौरान यह घटकर 27% रह गया। डीजीसीआईएस आंकड़ों के अनुसार अन्य देशों से आयातों की औसत सीआईएफ कीमत क्षति अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान सम्बद्ध देशों की कीमत की तुलना में बहुत कम थी और केवल 2004-05 में अधिक थी। जाँच अवधि में यद्यपि देशों की तुलना में अन्य देशों से आयातों की दर कम थी तथापि उनके बीच का अंतर उल्लेखनीय था। दूसरी ओर निर्यातकों की सूचना पर आधारित आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जाँच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से आयातों के मामले में इकाई दर कम थी।

65. सम्बद्ध देशों के आयातों को मिला दिया गया है और अलग-अलग देशों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

आयात	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि <sup>1</sup>	जाँच अवधि <sup>2</sup>
ईयू से आयात					
मात्रा (मी. टन)	390.36	420.00	332.43	1418.17	कोई उत्तर नहीं
मूल्य (लाख रु.)	256.70	267.12	267.79	1175.23	
कीमत/मी. टन	65759	63600	80556	82870	
पाटित आयातों में हिस्सा	66.54	12.89	5.45		12.80
कुल आयातों में हिस्सा	4.10	4.00	2.56		9.30
जापान से आयात					
मात्रा (मी. टन)		5.82	32.00		कोई उत्तर नहीं
मूल्य (लाख रु.)		3.31	20.53		

कीमत/मी. टन		56816	64161		
पाटित आयातों में हिस्सा		0.18	0.52		
कुल आयातों में हिस्सा		0.06	0.25		
<b>सिंगापुर से आयात</b>					
मात्रा (मी. टन)	196.26	2781.14	2159.47	4434.00	5888.12
मूल्य (लाख रु.)	89.69	1542.96	1441.38	3696.34	4581.08
कीमत/मी. टन	45699	55479	66747	83364	77802
पाटित आयातों में हिस्सा	33.46	85.34	35.40		53.16
कुल आयातों में हिस्सा	2.06	26.51	16.62		38.61
<b>यूएसए से आयात</b>					
मात्रा (मी. टन)		52.00	3577.10	3769.96	कोई उत्तर नहीं
मूल्य (लाख रु.)		31.64	2433.85	3073.51	
कीमत/मी. टन		60848	68040	81526	
पाटित आयातों में हिस्सा		1.60	58.63		
कुल आयातों में हिस्सा		0.50	27.53		24.72

टिप्पणी: जाँच अवधि<sup>1</sup>: डीजीसीआईएस के आँकड़े; जाँच अवधि<sup>2</sup>: निर्यातकों के आँकड़े.

66. प्राधिकारी ने नोट किया कि :-

- ईयू का हिस्सा, जो आधार वर्ष में सम्बद्ध देशों से कुल आयातों का 66.5% था, घटकर 2004-05 में 6% रह गया परन्तु जाँच अवधि में बढ़कर लगभग 13% हो गया। कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में ईयू से आयात, जो 2002-03 में 4.1% थे, 2004-05 में घटकर 2.56% रह गए और जाँच अवधि में पुनः बढ़कर 9.30% हो गए।
- 2002-03 में और जाँच अवधि में जापान से आयात शून्य था और अंतरिम अवधि में नगण्य था।
- सिंगापुर से आयात 2002-03 में प्रतिशत के रूप में अत्यधिक अर्थात् 85% थे, परन्तु जाँच अवधि के दौरान 53% थे। कुल आयातों में इसका हिस्सा आधार वर्ष अर्थात् 2003-04 की तुलना में 10 गुना बढ़ गया, 2004-05 में घटकर 16% रह गया और जाँच अवधि के दौरान बढ़कर 39% हो गया।
- यूएसए से आयात जो 2003-04 में मात्र 1.6% थे, बढ़कर 2004-05 में 59% हो गए और जाँच अवधि में ये पाटित आयातों के 34% थे। कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में यूएसए का हिस्सा जाँच अवधि में लगभग 25% बनता था।

67. निम्नलिखित विश्लेषण में आयातों के मूल्य तथा घरेलू माँग के आकलन के लिए डीजीसीआईएस के सौदेवार माँग के आकलन के लिए डीजीसीआईएस के सौदेवार आँकड़ों का उपयोग किया गया है, सिवाय जाँच अवधि के, जिनमें निर्यातकों के आँकड़े प्रयुक्त किए गए हैं। तथापि, जापान से आयातों को शामिल नहीं किया गया है।

(क) आयातों की मात्रा

68. जहाँ तक पाटित आयातों की मात्रा का प्रश्न है, यह जाँच की गई कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

69. सम्बद्ध वस्तुओं की घरेलू खपत/माँग की गणना के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा को भारत में कुल आयातों में जोड़ दिया गया है।

मानदण्ड (मी. टन में)	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि <sup>1</sup>
कुल आयात	9531	10492	12992	12199
सूचीबद्ध	100	110	136	128
सम्बद्ध देशों से आयात	587	3253	6069	8861
सूचीबद्ध	100	555	1039	1510
घरेलू उद्योग की बिक्री	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	124	114	125
घरेलू माँग	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	116	126	126
घरेलू उत्पादन	***	***	***	***

टिप्पणी: आनुपातिक आधार पर वार्षिकीकृत; स्रोत: घरेलू उद्योग, डीजीसीआईएस

70. प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू माँग (सूचीबद्ध) में, घरेलू बिक्री में 125 तथा कुल आयातों में 128 की तुलना में क्षति अवधि में 126 की वृद्धि हुई जबकि उक्त अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से कुल आयातों में 14 गुना वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा 2004-05 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान जहाँ कुल आयातों में भारी गिरावट आई, वहीं क्षति अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से कुल आयातों में 14 गुना वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, 2004-05 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान जहाँ कुल आयातों में भारी गिरावट आई, वहीं क्षति अवधि के अंतिम दो वर्षों में घरेलू माँग स्थिर बनी रही, वहीं सम्बद्ध देशों के आयातों में इस समस्त अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि का रुख बना रहा। घरेलू बिक्री में 2004-05 में आई गिरावट परन्तु जाँच अवधि के दौरान फिर बहाल हो गई हालांकि दो वर्षों में माँग उसी स्तर पर बनी रही थी।

(ख) घरेलू उद्योग की बिक्री एवं बाजार हिस्से पर वास्तविक तथा सम्भावित प्रभाव :

प्रतिशत हिस्सा	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि <sup>1</sup>
घरेलू माँग में				
क) सम्बद्ध देशों से आयात	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	476	822	1194
ख) अन्य आयात	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	69	62	30
ग) कुल आयात	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	95	108	101
घ) घरेलू उद्योग	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	106	90	99
पाटित आयात/घरेलू उद्योग का उत्पादन	7.44	32.34	59.32	89.13

टिप्पणी: जाँच अवधि<sup>1</sup>: डीजीसीआईएस के अंकड़े; स्रोत: घरेलू उद्योग, डीजीसीआई एण्ड एस

71. प्राधिकारी ने नोट किया कि माँग में घरेलू उद्योग का हिस्सा 2002-03 में 46.7% से 0.6% घटकर जाँच अवधि के दौरान लगभग 46.1% रह गया था, जबकि कुल आयातों में तदनुरूप वृद्धि हुई थी। अन्य

देशों से आयातों का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान 50% से घटकर 14.8% हो गया और यह गिरावट सम्बद्ध देशों के आयातों में पूर्णतः समाहित हो गई। इसके परिणामस्वरूप आधार वर्ष के दौरान सम्बद्ध देशों से आयातों की मात्रा में यद्यपि कई गुना वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू माँग के प्रतिशत के रूप में “पाटित आयातों” में वृद्धि अन्य देशों के आयातों से अधिक हो गई, परन्तु घरेलू उद्योग की तुलना में उतनी नहीं हुई।

ग) घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग पर वास्तविक एवं सम्भावित प्रभाव

72. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जाँच इसकी क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं इन मानदण्डों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संदर्भ में की गई है।

मानदण्ड	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि
क्षमता	11250	11250	11250	11250
उत्पादन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	128	130	126
क्षमता उपयोग (%)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	128	130	126
घरेलू माँग (मी. टन)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	116	126	126

टिप्पणी: जाँच अवधि<sup>1</sup>: डीजीसीआईएस के आंकड़े; स्रोत: घरेलू उद्योग, डीजीसीआई एण्ड एस

73. प्राधिकारी ने नोट किया कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान माँग में वृद्धि हुई, तथापि घरेलू उद्योग की स्थापना क्षमता अपरिवर्तित बनी रही। क्षमता उपयोग में (सूचीबद्ध) 2004-05 में 130 तक वृद्धि होने के बाद जाँच अवधि के दौरान 4 की मामूली गिरावट आई। गिरावट के बावजूद क्षमता उपयोग आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान 18% बढ़ गया। प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उत्पादन घरेलू माँग का लगभग आधा था, अतः आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए आयात जरूरी हो गए।

च.2.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क) कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री

74. जहाँ तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का प्रश्न है, प्राधिकारी से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे पाटित आयातों के प्रभाव का उद्देश्य कीमतों में अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक मंदी लाना अथवा कीमत में बढ़ोत्तरी को रोकना है, जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक होती।

75. इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ यह जाँच करने के लिए कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण उल्लेखनीय कीमत कटौती अथवा कम कीमत पर बिक्री हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के कारण कीमत में मंदी आई है अथवा कीमत में वृद्धि पर रोक लगी है जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक होती, घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) तथा क्षतिरहित कीमत की तुलना सम्बद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।



76. कीमत कटौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की भारत औसत कारखाना द्वार एन एस आर के साथ पाटित आयातों के पहुँच मूल्य की तुलना करके किया गया है जबकि दी गई रिबेटों, छूटों, कमीशनों और अदा किए गए शुल्क को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कम कीमत पर बिक्री के विश्लेषण हेतु पाटित आयातों के पहुँच मूल्य की तुलना संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत, जिसे उद्योग की सत्यापित लागत और एस जी ए व्ययों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ निर्धारित किया गया था, के साथ की गई थी। कीमत ह्रास एवं न्यूनीकरण प्रभावों की जाँच के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्तियों की प्रवृत्ति की तुलना बिक्रियों की लागत के साथ की गई थी।

मापदण्ड (रुपए/मी.टन)	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि
पहुँच कीमत	77530	68616	82738	92191
सूचीबद्ध	100	89	107	119
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	103	125	136
बिक्री लागत	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	94	102	112
कीमत कटौती <sup>1</sup>	***	***	***	***
कीमत कटौती %	(15-20%)	(0-5%)	(0-5%)	(0-5%)
क्षति रहित कीमत				***
कम कीमत पर बिक्री <sup>2</sup>				***
कम कीमत पर बिक्री %				15-20%

नोट: 1. एन एस आर ऋण आयातों की पहुँच कीमत 2. एन आई पी ऋण पहुँच मूल्य

स्रोत: घरेलू उद्योग, डी जी सी आई एण्ड एस

77. प्राधिकारी ने नोट किया कि संचयी आधार पर संबद्ध देश के आयातों के सूचीबद्ध पहुँच मूल्य में 2002-03 के बाद 119 तक और निवल बिक्री प्राप्ति में 136 तक की वृद्धि हुई थी। जाँच अवधि के प्रत्येक वर्ष में, पहुँच मूल्य निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक रहा था, इस प्रकार कोई कीमत कटौती नहीं हुई है। प्रकटन के बाद घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि कीमत कटौती का संचयी विश्लेषण भ्रमपूर्ण होगा और कीमत कटौती संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रत्येक सौदे की तुलना घरेलू कीमत से करनी चाहिए। तथापि, प्राधिकारी ने नोट किया कि जहाँ अनेक देशों से आयातों की एक साथ जाँच की जाती है वहाँ क्षति एवं कारणात्मक संबंध का विश्लेषण संचयी रूप से किया जाता है। वर्ष 2003-04 को छोड़कर, पहुँच मूल्य बिक्रियों की लागत से भी अधिक रहा है। प्राधिकारी ने यह भी देखा है कि पहुँच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत इसी दिशा में रही है। घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण 92191 रूपए के पहुँच मूल्य के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, सीए सं. : 1294/2001 के अनुपालन में जाँच अवधि में \*\*\* रूपए प्रति मी. टन के रूप में किया गया है ताकि कम कीमत पर बिक्री 15-20% के बीच रहे। वांछनीय बिक्री कीमत के घरेलू उद्योग का अपना आंकड़ा \*\*\* रूपए है। इस कीमत पर, कम कीमत पर कुल बिक्री केवल 0 - 3 प्रतिशत तक होगी। इसके अलावा एन एस आर (सूचीबद्ध) में बिक्रियों की लागत में 112 की तुलना में 136 की वृद्धि हुई है इस प्रकार कोई कीमत ह्रास नहीं हुआ है। इसके अलावा, यद्यपि क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में स्थिति पूर्णतः बदल गई इस प्रकार कीमत न्यूनीकरण भी नहीं हुआ है।

**छ.3 क्षति संबंधी अन्य कारकों की जाँच**

78. कुछ कारकों अर्थात् क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों और बाजार हिस्से में वास्तविक और संभावित गिरावट की आयातों की मात्रा में वास्तविक और संभावित वृद्धि के साथ पिछले खण्ड में जाँच की गई थी और यह नोट किया गया था कि

- ❖ घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2004-05 तक भारी वृद्धि के बाद जाँच अवधि में मामूली कमी आई थी ।
- ❖ जाँच अवधि में क्षमता उपयोग में 3 प्रतिशत की कमी आई ।
- ❖ घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वर्ष 2004-05 में गिरावट के बाद जाँच अवधि में काफी वृद्धि हुई है, यद्यपि माँग समान स्तर पर रही है ।

**(क) लाभ पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव**

79. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की स्थिति निम्नानुसार रही है:-

मापदण्ड (लाख रुपये में)	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि <sup>1</sup>
घरेलू उद्योग की बिक्री लागत	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्तियाँ	***	***	***	***
लाभ/हानि (रुपये/मी.टन) <sup>2</sup>	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(31)	49	44
घरेलू बिक्रियों पर लाभ/हानि	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(39)	56	55
ब्याज	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	94	62	10
पी बी आई टी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(70)	175	182

नोट: 1. आनुपातिक आधार पर वार्षिकीकृत  
2. बिक्री प्राप्ति - बिक्री लागत

स्रोत: घरेलू उद्योग

80. यद्यपि क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में बिक्री लागत, बिक्री प्राप्ति से अधिक रही थी, तथापि जैसा कि बढ़ते हुए लाभों से प्रदर्शित होता है । वर्ष 2004-05 में घरेलू उद्योग के निष्पादन की स्थिति पूर्णतः बदल गई थी ।

**(ख) रोजगार और मजदूरी पर वास्तविक और संभावित प्रभाव**

81. घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर निम्नानुसार रहा है:

मापदण्ड	2002-03	2003-04	2004-05	POI <sup>1</sup>
कर्मचारी (सं०)	***	***	***	***
मजदूरी (लाख रुपये)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	102	106	110

टिप्पणी: आनुपातिक आधार पर वार्षिकीकृत, स्रोत: घरेलू उद्योग

प्राधिकारी ने नोट किया कि संबद्ध उत्पाद के उत्पादन हेतु रोजगार स्तर वर्ष 2002-2003 से स्थिर रहे हैं, परन्तु चूँकि घरेलू उद्योग बहु-उत्पाद उद्योग था इसलिए रोजगार का स्तर क्षति का निर्णायक संकेतक नहीं हो सकता है। मजदूरी में भी निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई थी। अतः यह मापदण्ड घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं था।

**(ग) उत्पादकता पर वास्तविक और संभावित प्रभाव**

82. प्राधिकारी ने नोट किया कि प्रति कर्मचारी उत्पादकता और बिक्रियों में वर्ष 2004-05 तक वृद्धि हुई थी। जाँच अवधि में उत्पादकता में उत्पादन में गिरावट के कारण मामूली कमी आई थी।

मापदण्ड	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि <sup>1</sup>
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	128	130	126
प्रति कर्मचारी बिक्रियाँ (रुपये में)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	120	142	170

टिप्पणी: आनुपातिक आधार पर वार्षिकीकृत, स्रोत: घरेलू उद्योग

**(घ) नकद प्रवाह, लाभ और निवेश पर आय पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव**

83. चूँकि घरेलू उद्योग एवं बहु उत्पाद कंपनी था, इसलिए क्षति प्रयोजनों हेतु पूरी कंपनी के नकद प्रवाह की जाँच करना उचित नहीं हो सकता है। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की नकद लाभ की स्थिति, लगाई गई पूंजी और निवेशों पर आय की जाँच की है।

मापदण्ड (लाख रुपये में)	2002-03	2003-04	2004-05	जाँच अवधि <sup>1</sup>
पी बी टी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(39)	56	55
मूल्यहास	***	***	***	***
नकद लाभ	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(28)	79	79
पी बी आई टी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(70)	75	82
लगाई गई पूंजी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	96	92	79
लगाई गई पूंजी पर आय (%)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(31)	82	66

टिप्पणी: आनुपातिक आधार पर वार्षिकीकृत, स्रोत: घरेलू उद्योग

84. वर्ष 2004-05 में पी बी टी, पी बी आई टी और नकद लाभ सुधरकर घाटे की स्थिति से लाभ की स्थिति में पहुँच गए थे, जो जाँच अवधि में भी अपेक्षाकृत कम स्तर पर जारी रहा। इसी प्रकार लगाई गई पूंजी पर आय (% सूचीबद्ध) 2004-05 में बढ़कर 182 हो गई और जाँच अवधि में घटकर 166 रह गई थी।

**(ड.) माल सूचियाँ**

85. घरेलू उद्योग की माल सूची की स्थिति निम्नानुसार रही है:-

मापदण्ड (मी.टन में)	2002-03	2003-04	2004-05	POI <sup>1</sup>
माल सूची का औसत स्टाक	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	53	76	69
बिक्रियों के % रूप में	9.98	4.25	6.63	4.42

टिप्पणी: आनुपातिक आधार पर वार्षिकीकृत, स्रोत: घरेलू उद्योग

प्राधिकारी ने नोट किया कि औसत माल सूचियों में आधार वर्ष से जाँच अवधि में समग्र रूप से और बिक्रियों के प्रतिशत रूप दोनों में गिरावट आई है।

#### (च) पूँजी जुटाने का सामर्थ्य

86. प्राधिकारी के समक्ष यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घरेलू उद्योग पूँजी जुटाने के सामर्थ्य के संबंध में समस्याओं का सामना कर रहा है।

#### (छ) वृद्धि

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष से जाँच अवधि में माँग में वृद्धि और उत्पादन, बिक्रियों, लाभ, नकद प्रवाह तथा निवेशों पर आय जैसे मापदण्डों की दृष्टि से घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।

#### (ज) पाटन मार्जिन की मात्रा

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के संकेतक के रूप में संबद्ध देशों से पाटन मार्जिनों को केवल अमरीका के मामले में काफी अधिक पाया गया है।

#### छ.4 समग्र आकलन

89. कारकों के उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि आयात की काफी अधिक मात्रा के बावजूद घरेलू उद्योग बाजार में अपना हिस्सा बनाए रखने में सक्षम रहा है और संगत अवधि के दौरान उसे क्षति नहीं उठानी पड़ी है क्योंकि अधिकांश मापदण्डों में आधार वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। संबद्ध देश से आयातों के कारण कोई कीमत कटौती, कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है, परन्तु 19 प्रतिशत की कम कीमत पर बिक्री देखी गई है।

#### छ.5 क्षति संबंधी निष्कर्ष

90. प्राधिकारी ने नोट किया कि संबद्ध देश से आयातों का मात्रात्मक प्रभाव समग्र रूप से उनमें वृद्धि के बावजूद अपेक्षाकृत कम रहा है और कीमत प्रभाव कम कीमत पर बिक्री तक सीमित रहा है। घरेलू उद्योग के अधिकांश मापदण्ड क्षति नहीं दर्शाते हैं। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी नहीं है।

**ज. कारणात्मक संबंध****ज.1. हितबद्ध पक्षों के विचार**

91. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध होना चाहिए; जो वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार पूर्णतः अनुपस्थित था। घरेलू उद्योग ने यह बताते हुए इस अनुरोध को खारिज किया है कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में समग्र रूप से संबद्ध वस्तु सहित सभी उत्पादों के ब्यौरे दिए जाते हैं इसलिए उन पर आधारित कोई विश्लेषण उचित नहीं होगा। इसके अलावा, निर्णायक समीक्षा में कारणात्मक संबंध के विश्लेषण का कोई परिणाम नहीं निकला था क्योंकि यह मूल जाँच में सिद्ध हुआ था और इनका पुनः आकलन करने की आवश्यकता नहीं है।

92. अनारोपण के मुद्दों पर, अनिवार्य कारकों की निम्नानुसार जाँच की गई है :-

- माँग में संकुचन :- क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की माँग में वृद्धि हुई है और जाँच अवधि में यह स्थिर रही थी।
- उपभोग की प्रवृत्ति :- किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपभोग की प्रवृत्ति में किसी खास बदलाव का आरोप नहीं लगाया गया है।
- अन्य देशों से आयात :- संबद्ध देशों से इतर देशों के मूल के संबद्ध उत्पाद के कुल आयात घट रहे हैं और संबद्ध देश से बढ़ते हुए आयात इनका स्थान ले रहे हैं।
- प्रतिस्पर्धा की स्थिति :- ये वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।
- प्रौद्योगिक में विकास :- हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पुरानी और अक्षम है परन्तु उद्योग ने यह कहते हुए इसका खण्डन किया है कि विनर्माण की प्रौद्योगिकी विश्व भर में एक समान है।
- यह आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग जो जल की अल्पता वाले क्षेत्र में स्थित है, जबकि संबद्ध उत्पाद जल-गहन है, को स्थान संबंधी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

**ज.2. कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक**

93. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जाँच से पता चलता है कि निष्पादन संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण प्रभावित नहीं हुआ है। पाटित आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में 35% से अधिक की वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान केवल 0.6% की कमी आई है। माँग में वृद्धि को आयातों द्वारा पूरा किया गया है लेकिन संबद्ध देश के आयातों ने अन्य देशों से हुए आयातों को बाजार से बाहर कर दिया है। कोई कीमत कटौती नहीं हुई है परन्तु लगभग 19% कम कीमत पर बिक्री हुई है। घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है। उत्पादन और उसके कारण क्षमता उपयोग में मामूली गिरावट आई है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर आय की स्थिति में लगातार सुधार के बाद जाँच अवधि में आंशिक रूप से विकृति आई है।

94. उपर्युक्त अनारोपण विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों से, उनके मात्रात्मक एवं कीमत प्रभावों के जरिए घरेलू उद्योग को कोई खास क्षति नहीं हुई है। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति काफी कम और अवास्तविक है।

### अ. क्षति एवं क्षति मार्जिन की मात्रा

#### अ.1. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

95. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से कैप्टिव निविष्टियों की अंतरण कीमत (बाजार मूल्य) के आधार पर क्षति रहित कीमत के निर्धारण हेतु मै. आरआईएल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2006{202 ईएलटी 23 (एससी)}] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखने का अनुरोध किया है। डीपीएफ ने इसके विपरीत यह माना है कि एनआईपी के निर्धारण में प्राधिकारी को कैप्टिव निविष्टियों की वास्तविक लागत, जैसी कि घरेलू उद्योग के लेखों में प्रदर्शित है एवं प्राधिकारी द्वारा सत्यापित है, को ध्यान में रखना चाहिए। यह कि इस निर्णय पर जताया गया भरोसा अब समाप्त हो गया है चूँकि यह मानने में कि निविष्टियों की बाजार कीमत को लिया जाना चाहिए, न्यायालय का तर्क इस बात पर आधारित था कि घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से, और घरेलू उद्योग के एक से अधिक घटक के लिए केवल एक एनआईपी निर्धारित की गई थी ताकि अन्य को अलग किया जाएगा यदि किसी एक संघटक के मामले में अंतरण कीमत और निविष्टियों का कैप्टिव रूप से उत्पादन करने वाले अन्य संघटकों के लिए निविष्टियों की लागत ली जाती है। परन्तु चूँकि याचिकाकर्ता संबद्ध उत्पाद का एकमात्र विनिर्माता था। इसलिए घरेलू उद्योग के संघटकों के बीच भेदभाव का प्रश्न नहीं उठ सकता था। इस प्रकार एनआईपी का निर्धारण केवल याचिकाकर्ता के लिए किया जाना था।

96. तथापि प्राधिकारी ने एनआईपी का निर्धारण पूर्वोक्त निर्णय में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और अन्य संबंधित लागतों को ध्यान में रखते हुए किया है, जो 114351 रु. प्रति मी. टन बनती है। संबद्ध देशों से क्षति मार्जिन निम्नानुसार बनता है :-

#### क्षति मार्जिन (रु./मी.टन)

क्षति रहित कीमत		पहुँच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %
***	अमेरिका	94281	***	15-20%
	ईयू	95834	***	15-20%
	सिंगापुर		***	
	एसईपीएल	***	***	27-33%
	बीएसईए	***	***	27-33%
	अन्य	***	***	30-35%
	जापान	जाँच अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं		
	कुल	92191	***	18-23%

## अ. पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना

97. अधिनियम की धारा 9क में समाप्ति संबंधी समीक्षा में प्राधिकारी के लिए यह जाँच करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहेंगे या उनकी पुनरावृत्ति होगी।

### 1. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

98. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी निर्यातकों ने पाटन जारी रखा है और वे इसकी मात्राओं में वृद्धि कर रहे हैं, यदि शुल्क हटाया जाता है तो इसमें और वृद्धि होगी। उन्होंने दावा किया है कि कच्ची सामग्री, पीओ का आयात संबद्ध उत्पाद की कीमतों से उच्चतर कीमतों पर किया गया है यद्यपि पीओ की आवश्यकता कुल एफएसपी भार का लगभग 90% होती है। एफएसपी की कीमतें पीओ की कीमतों से 35% तक कम रही है जिससे जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों द्वारा अत्यधिक पाटन का संकेत मिलता है, जो यदि शुल्क की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो भविष्य में जारी रहेगा और बढ़ेगा और उद्योग को नुकसान पहुँचाएगा। डीजीसीआई एण्ड एस के आयात आँकड़ों से यह पता चला कि पीओ हेतु भारत को पहुँच मूल्य संबद्ध उत्पाद से अधिक था जिससे घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की अत्यधिक आशंका बन जाती है।

99. इसके उत्तर में, एसईपीएल ने अनुरोध किया है कि कच्ची सामग्रियों के आयात पर विचार करना प्रासंगिक नहीं है और यदि ऐसा किया भी जाता है तो जैसाकि आईसीआईएस के प्रकाशन, जिसमें यह दर्शाया गया था कि भारत में पीओ की कीमत उपलब्ध नहीं है, से स्पष्ट है भारत में कोई तैयार बाजार नहीं था; यह कि डीजीसीआई एण्ड एस के आँकड़ों में पीओ की उल्लिखित कीमत सिंगापुर में पीओ की सांकेतिक कीमत नहीं थी क्योंकि उसमें दर्शाया गया था कि (क) वर्ष के दौरान काफी कम मात्रा का आयात किया जा रहा है; (ख) प्रत्येक देश से पीओ की इकाई कीमत में काफी अंतर है और (ग) ये पीओ के लिए एशियाई बाजार का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इस बात का खण्डन करते हुए कि एसईपीएल से संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू उद्योग प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है, एसईपीएल ने यह आरोप लगाया है कि कोई भी कथित कीमत कटौती/ह्रास घरेलू उद्योग द्वारा बाजार में अपनी एकाधिकारी स्थिति बनाए रखने और कीमतें कम करके प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करने के प्रयास के कारण हो सकता है। उन्होंने भारत को एफएसपी का निर्यात सिंगापुर में उसकी घरेलू कीमतों से अधिक कीमत पर और लाभ के लिए किया है।

100. डीपीएफ ने यह रेखांकित किया है कि निर्णायक समीक्षा की विषय वस्तु पालिओल के आयात थे न कि पीओ के आयात। पीओ की मात्रा और आयात यह निर्धारित करने का आधार नहीं है कि क्या पालिओल पर पाटनरोधी शुल्क लागू रहना चाहिए, या और कोई मामला, जबकि जाँच अवधि के दौरान पालिओल के आयात हुए हैं और पालिओल के सामान्य मूल्य के निर्धारण में कुछ निर्यातक प्राधिकारी के साथ सहयोग कर रहे थे। यदि सामान्य मूल्य निर्धारित हो जाता है, तब भी कच्ची सामग्री की कीमतें वे होंगी जो निर्यातक देश में हैं, न कि भारत में आयात कीमतें।

## 2. प्राधिकारी द्वारा जाँच

101. कच्चे माल के आयातों की कीमतों से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर घरेलू उद्योग पाटन तथा क्षति की संभावना संबंधी अपने दावे को प्रमाणित नहीं कर सका है। खुलासे के बाद घरेलू उद्योग ने इसकी जिम्मेदारी हितबद्ध पक्षों तथा प्राधिकारी पर डाल दी है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी को संमुचित मूल्यांकन करना है तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचना है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से कोई क्षति होने की संभावना नहीं है और अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री शुल्क विस्तार हेतु उचित कारण थी।

102. प्राधिकारी ने यह पाया कि मौजूदा हालात में जाँच अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयात अन्य देशों से हुए आयातों को पीछे छोड़ते हुए काफी अधिक मात्रा में दर्ज किए गए थे। तथापि आयातों में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान अपना बाजार हिस्सा बनाए रखा है ताकि वर्तमान में कोई क्षति न हो सकें। इसके अलावा घरेलू उद्योग की क्षमता घरेलू माँग की केवल लगभग आधी है अतः इस कमी को पूरा करने के लिए आयात अनिवार्यतः अपेक्षित हैं। प्राधिकारी ने इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया कि क्षति अवधि के दौरान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जहाँ तक कीमत पर संबद्ध देश के आयातों के प्रभाव का संबद्ध है, कीमत में कोई कटौती, कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है। एनआईपी की गणना हेतु उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर जाँच अवधि में 19% की कम कीमत पर बिक्री हुई है जो कि उद्योग के अपने निर्धारण से काफी अधिक है।

103 संभावित परिदृश्य का आंकलन करने में आयात आंकड़ों तथा कीमतों के देश वार विश्लेषण में निम्नलिखित बातों का पता चलता है :-

- ❖ प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क के अधिरोपण के बावजूद अमेरिका से पाटित कीमतों पर आयात हो रहे हैं क्योंकि जाँच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन को अत्यधिक पाया गया है। आयात कीमतों की प्रवृत्ति से यह प्रदर्शित होता है कि अमरीकी आयातों की सीआईएफ कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है जो 2003-04 में 100 (2002-03 में शून्य आयात) से बढ़कर जाँच अवधि में 134 हो गई है किन्तु क्षति अवधि के दौरान सीमाशुल्क 2002-03 में 30% से घटकर जाँच अवधि में 14.5 प्रतिशत हो गया है, जाँच अवधि में पहुँच मूल्य में प्रवृत्ति में 128 की कम वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन पहुँच मूल्य 2004-05 में और जाँच अवधि के दौरान 1597.49 डॉलर प्रति मी.टन की संदर्भ कीमत से उत्तरोत्तर अधिक था। निर्यातक के उत्तर के अभाव में अमरीका के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करना पड़ा तथा जाँच अवधि के दौरान पाटन



मार्जिन काफी अधिक रहा है। यद्यपि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद की पहुँच कीमत मूल जाँच में निर्धारित संदर्भ कीमत से काफी अधिक है तथापि जाँच अवधि में अमरीका से मूल कच्ची सामग्री अर्थात् प्रोपीलिन आक्साईड जिसकी लागत संबद्ध वस्तु की लागत का लगभग 80% बनती है, का आयात संबद्ध उत्पाद के आयात की सीआईएफ कीमत से अधिक कीमत पर किए गए हैं जिससे वर्तमान पाटन तथा सतत पाटन की संभावना का पता चलता है। इसके अलावा अमरीका से हुए आयातों की मात्रा में प्रवृत्ति से 2003-04 में 100 से जाँच अवधि में 7250 की वृद्धि प्रदर्शित होती है। अतः अधिकारी का यह मत है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में अमेरिका से पाटित आयातों के जारी रहने की संभावना है।

- ❖ ईयू के मामले में वर्तमान पाटन मार्जिन शून्य है। परंतु पाटित आयात जारी रहे हैं और मात्रा में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में सूचकांकित सीआईएफ कीमत 100 से बढ़कर 126 हो गई है जबकि पहुँच मूल्य (सूचकांकित) 100 से बढ़कर 111 हो गया है। पहुँच मूल्य क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में पर्याप्त मार्जिन तक संदर्भ कीमत से अधिक रहा है। निर्यातक के उत्तर के अभाव में सामान्य मूल्य का परिकलन करना पड़ा और जाँच अवधि में पाटन मार्जिन काफी अधिक रहा है। जहाँ तक ईयू से कच्ची सामग्री के आयात की दर का संबंध है आँकड़ों से अन्य देशों की तुलना में असामान्य रूप से उच्च दरें प्रदर्शित होती हैं और इस प्रकार कुल पीओ आयातों की भारित औसत दर लागू की गई है। विश्लेषण से यह पता चलता है कि जहाँ पीओ के आयात की औसत सीआईएफ दर क्षति अवधि की पूर्ववर्ती तीन वर्षों में संबद्ध उत्पाद की कीमत से काफी कम थी वहीं जाँच अवधि में स्थिति बदल गई है। तथापि, अलग से एक वर्ष के लिए प्रवृत्ति से ईयू से पीओ तथा संबद्ध वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। अतः इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ईयू की कीमत उस देश के लिए समग्र क्षति अवधि के लिए निर्धारित संदर्भ कीमत से काफी अधि रही है, शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में इस प्रवृत्ति में बदलाव आने की कम संभावना है। अतः प्राधिकारी का यह मत है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में ईयू से आसन्न गहन पाटन या उसके पुनः प्रारंभ होने की संभावना कम है।

- ❖ सिंगापुर के मामलों में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी निर्यातकों के लिए वर्तमान पाटन मार्जिन का शून्य पर निर्धारण उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में निर्धारित एकल देश विनिर्दिष्ट सामान्य मूल्य के आधार पर किया गया है। उपर्युक्त आधार पर निर्धारित अपशिष्ट पाटन मार्जिन भी नकारात्मक परिकलित हुए हैं। तथापि सिंगापुर से आयात कीमतों से यह प्रदर्शित होता है कि क्षति अवधि के दौरान सीआईएफ कीमत 100 से बढ़कर 170 और पहुँच मूल्य 100 से बढ़कर 150 हो गया। परंतु क्षति अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान पहुँच मूल्य संदर्भ कीमत से कम था और 2004-05 तथा जाँच अवधि में ही कीमतें संदर्भ कीमत से अधिक हुई हैं। कच्ची सामग्री की दरों के संबंध में जाँच अवधि के दौरान सिंगापुर से पीओ के आयातों में असामान्य प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति तथा उसी देश से मूल कच्ची सामग्री की निर्यात कीमत से यह संकेत मिलता है कि जाँच अवधि के दौरान कीमत प्रवृत्ति सतत धारणीय या स्थायी प्रकृति की नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगापुर से आयातों में वृद्धि 2002-03 में 100 से बढ़कर जाँच अवधि के दौरान 3000 हो गई। इसके अलावा, सहयोगी निर्यातकों की संबद्ध उत्पाद का उत्पादन क्षमताएं अत्यधिक हैं और यदि निर्यातक देशों में संबद्ध उत्पाद के व्यापार की दिशा में कोई बदलाव होता है तो बढ़ती हुई घरेलू मांग के कारण आयातों का हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगा। अतः

प्राधिकारी का अभिमत है कि शुल्क हटा लिए जाने की स्थिति में इसे देश से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

- ❖ जहाँ तक जापान का प्रश्न है, पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में कोई आकलन नहीं किया जा सका। जिन दो वर्षों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से एक वर्ष के दौरान पहुँच मूल्य सन्दर्भ मूल्य से कम तथा दूसरे वर्ष के दौरान यह संदर्भ मूल्य से अधिक था। प्रॉपीलीन की कीमतों की प्रवृत्ति 100 से बढ़कर 154 हो गई। 2003-04 में संबद्ध उत्पाद के आयात की दर कच्चे माल के आयात की दर से 4000/-रुपये अधिक थी, परंतु वर्ष 2004-05 में यह अंतर घटकर 800 रुपये हो गया। आयातों की मात्रा की प्रवृत्ति 2003-04 में 100 से बढ़कर अगले वर्ष 150 हो गई। संबद्ध देशों की निर्यात कीमत में औसत वृद्धि का प्रयोग करके वर्ष 2004-05 की निर्यात कीमत के आधार पर जाँच अवधि के दौरान निर्यात कीमत का अनुमान लगाया गया था पिछले वर्ष की कीमत प्रवृत्ति को देखते हुए अनुमानित आंकड़े जापान की संभावित निर्यात कीमत दर्शाते हैं और इस निर्यात कीमत की तुलना संरचित सामान्य मूल्य से करने पर ज्ञात होता है कि पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन अत्यधिक है। अतः प्राधिकारी का अभिमत है कि शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में जापान से पाटन की पुनरावृत्ति की आसन्न संभावना है।

104. कुल मिलाकर देशवार वर्तमान तथा सम्भावित परिदृश्य निम्नानुसार है :-

- ❖ यूएसए वर्तमान में पाटन किया जा रहा है और पाटन जारी रहने की संभावना है, परिणामतः घरेलू उद्योग को होगी;
- ❖ ईयू: वर्तमान में पाटन नगण्य है और पाटन बढ़ने तथा परिणामतः घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना कम है;
- ❖ सिंगापुर: वर्तमान में पाटन नगण्य है परंतु पाटन के बढ़ने की संभावना है, परिणामतः घरेलू उद्योग को क्षति होगी;
- ❖ जापान: आकलन करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परंतु निर्यात कीमत के अनुमान के आधार पर पाटन की संभावना प्रतीत होती है।

### भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आम तौर पर पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और इस प्रकार उनकी संबंधित प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है तथापि उनके लागू होने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## ट. निष्कर्ष

106. उठाए गए मुद्दों की जाँच के बाद और वर्तमान पाटन एवं क्षति के विश्लेषण और पाटन एवं क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :-

(i) अमरीका से संबद्ध वस्तुओं ने सामान्य मूल्य से कम कीमत पर प्रवेश किया है और आयातित संबद्ध वस्तु के पाटन मार्जिन काफी अधिक हैं; जबकि यूरोपीय संघ और सिंगापुर से आयातित संबद्ध वस्तुओं की वर्तमान पाटन मार्जिन नगण्य है।

(ii) यदि शुल्क हटाया जाता है तो अमरीका से पाटन जारी रहने और सिंगापुर एवं जापान से पाटन बढ़ने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है; और यदि शुल्क वापस ले लिया जाता है तो ईयू से आयातों के बढ़ने की संभावना कम है।

(iii) इस समय घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण अत्यधिक वास्तविक क्षति हो रही है; परंतु यदि शुल्क हटाये जाते हैं तो क्षति की पुनरावृत्ति होने की आशंका है।

(iv) अतः पाटन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अमरीका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के विरुद्ध तथा पाटन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिंगापुर और जापान के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना जरूरी है।

## ठ. सिफारिशें

107. समीक्षा करने और इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि संबद्ध देशों से पाटन के जारी रहने और/या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है, प्राधिकारी की यह राय है कि चार देशों में से तीन देशों के आयातों के विरुद्ध उपाय को जारी रखना आवश्यक है। तथापि इन देशों से पाटन के वर्तमान स्तर पर विचार करते हुए प्राधिकारी की राय है कि लागू उपाय में संशोधन की जरूरत है। अतः प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे वर्णित ढंग एवं पद्धति से पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की सिफारिश करना आवश्यक मानते हैं।

108. अपेक्षाकृत कम शुल्क संबंधी नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी अमरीका और ईयू के मामले में क्षति अथवा पाटन के मार्जिन, जो भी कम हो के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू रखने की अनुशंसा करते हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि मूल जाँच में शुल्क संदर्भ कीमत के आधार पर लगाया गया था, प्राधिकारी यूएसए, सिंगापुर तथा जापान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हैं, जो निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में इंगित पहुँच मूल्य तथा संदर्भ कीमत के बीच अंतर के बराबर होगा, यदि आयात के समय पहुँच मूल्य कॉलम 9 में इंगित मूल्य से कम हो। इस प्रयोजनार्थ आयातों के पहुँच मूल्य का निर्धारण वस्तुओं का सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा आकलित मूल्य जमा मूल सीमाशुल्क के रूप में किया जाएगा।

क्र. सं.	उप-शीर्ष/टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	संदर्भ राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1.	3907.20	फ्लैक्सीबल स्लेबस्टॉक पॉलिओल	आणविक भार 3000-4000	अमरीका	कोई	कोई	कोई	2420.36	मी. टन	अम. डॉ.
2.	वही	वही	वही	यूरोपीय संघ, जापान और सिंगापुर को छोड़कर कोई	अमरीका	कोई	कोई	2420.36	मी. टन	अम. डॉ.
3.	वही	वही	वही	जापान	कोई	कोई	कोई	2391.96	मी. टन	अम. डॉ.
4.	वही	वही	वही	अमरीका, ईयू और सिंगापुर को छोड़कर कोई	जापान	कोई	कोई	2391.96	मी. टन	अम. डॉ.
5.	वही	वही	वही	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	कोई	1921.15	मी. टन	अम. डॉ.
6.	वही	वही	वही	अमरीका, जापान और सिंगापुर को छोड़कर कोई	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	1942.29	मी. टन	अम. डॉ.
7.	वही	वही	वही	सिंगापुर	कोई	शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम से इतर कोई उत्पादक	शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम एवं बीएसएफ साउथ इस्ट एशिया से इतर कोई निर्यातक	2023.10	मी. टन	अम. डॉ.
8.	वही	वही	वही	यूएसए, ईयू और जापान को छोड़कर कोई	सिंगापुर	कोई	शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम एवं बीएसएफ साउथ इस्ट एशिया से इतर कोई निर्यातक	2023.10	मी. टन	अम. डॉ.

### ड. आगे की प्रक्रिया

109. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

110. प्राधिकारी अधिनियम के संगत उपबंधों और इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार इसमें की गई सिफारिशों के अनुरूप निश्चयात्मक उपायों को जारी रखने, उनमें परिवर्तन या करने समाप्त करने की समय-समय पर समीक्षा करेंगे। ऐसी किसी समीक्षा के लिए किसी अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के भीतर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसे प्रस्तुत न किया जाए।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2007

**FINAL FINDINGS**

**Subject: Sunset Review of the definitive anti-dumping duty on imports of Flexible Slabstock Polyol originating in/exported from the European Union, Japan, Singapore and United States of America.**

**No. 15/25/2006-DGAD** - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules (hereinafter also referred as Rules), 1995, thereof;

**A. BACKGROUND**

2. WHEREAS, having regard to above Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated anti-dumping investigation on 21<sup>st</sup> September 2001 into alleged dumping of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter referred to as subject product/goods) originating in/exported from European Union (EU), Japan, Singapore and United States of America (USA) (hereinafter referred to as subject countries). Provisional antidumping duties were imposed on imports of the subject goods from the subject countries vide customs notification No: 17/2002-Customs dated 11<sup>th</sup> February 2002, based on the preliminary findings of the Authority dated 14<sup>th</sup> December 2001. The final findings of the Authority were published vide notification of 19<sup>th</sup> September 2002 and definitive anti dumping duties were imposed on the subject goods from the subject countries vide notification No: 120/2002-Customs dated 31<sup>st</sup> October 2002.

3. WHEREAS on the basis of a duly substantiated application filed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd, Chennai representing a major proportion of the domestic production of the subject product, the Authority initiated sunset review of the anti dumping duty on imports of the subject product originating from the subject countries vide notification dated 27<sup>th</sup> December 2006 under section 9A (5) of the Act, to examine whether the expiry of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. AND WHEREAS, vide Notification No: 12/2007- Customs dated 6<sup>th</sup> February 2007, the definitive duties were extended by the Central Government under Section 9A (5) for a period of one year up to 10<sup>th</sup> February 2008.

**B. PROCEDURE:**

5. The procedure described below has been followed:-

(i) As per sub-rule (5) of Rule 5 supra, the Authority notified the Embassies of subject countries in India about the receipt of fully documented application from the applicant before proceeding to initiate the review investigation;

(ii) In accordance with sub rule (2) of the rule 6 supra, the Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporting producers, importers, industry associations, the Embassies of the country concerned and to the applicants and gave them an opportunity to make their views known in writing.

(iii) According to sub-rule (4) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the relevant questionnaire to all the known exporters and the Embassies of subject countries in India and other interested parties.

(iv) The Embassies of subject countries in New Delhi was also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time.

(v) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following known exporters from the subject countries.

- ❖ Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd., Singapore.
- ❖ Bayer Polyurethane Asia (Pte) Ltd., Singapore.
- ❖ Sanyo Chemicals, Japan.
- ❖ Bayer Polyurethane Asia (Pte) Ltd, Germany.
- ❖ Repsol Quimica, S.A., Madrid, Spain.
- ❖ Dow Chemicals Co., Texas, United States of America

Only two exporters from Singapore, viz., Shell Eastern Petroleum Pte Ltd and BASF South-East Asia Pte Ltd responded to the exporter's questionnaire.

(vi) A copy of initiation notification along with the importers' questionnaire was also sent to the various importers listed in the application.

- ❖ Feather Foam Enterprises Pvt. Ltd, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli
- ❖ Natson Foam Mfg. P Ltd, Ahmedabad, Gujarat.
- ❖ Dura Foam Industries Pvt. Ltd, Silvassa, Dadra-Nagar Haveli
- ❖ Surya Foam, Pondicherry.
- ❖ DP Foam Private Ltd, Pondicherry/ Puducherry
- ❖ Kurlon Ltd, Bangalore, Karnataka.
- ❖ Aparna Polyproducts Ltd, Jaipur, Rajasthan.
- ❖ Tirupati Foams Ltd, Ahmedabad, Gujarat.
- ❖ Soft Foam Industries Pvt. Ltd, R.R District, Andhra Pradesh.

- ❖ Madras Polymoulds, Chennai, Tamil Nadu.
- ❖ Sheela Foam Private Ltd, Ghaziabad, Uttar Pradesh
- ❖ J.J. Foams Pvt. Ltd, Ghaziabad, U P
- ❖ M H Polymers Pvt, Ghaziabad, U P

However, complete response to the importers' questionnaire was received only from M/s DP Foam, Puducherry, after initial deficiencies were rectified. M/s Sheela Foam had provided a partial response without supporting documents despite request and therefore the submissions were disregarded.

(vii) Copies of initiation notice were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM, Excise Law Times etc., for wider circulation.

(viii) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation.

(ix) The investigation of dumping and injury covered the period from 1<sup>st</sup> April 2005 to 30<sup>th</sup> June 2006 (Also called the period of investigation or POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from 1<sup>st</sup> April 2002 to the end of POI (also called Injury period).

(x) The Authority sought and verified all the information it deemed necessary for the purpose of determination of dumping and resulting injury. The Authority conducted on-the-spot investigation of the domestic industry to the extent considered necessary. The cost of the production of the domestic industry was also analysed to work out the cost to produce and the cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles based on the information furnished by the applicants to ascertain if anti dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

(xi) The Authority held a public hearing on 13<sup>th</sup> August 2007 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, exporters and importers. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The written submissions received have been considered by the Authority in this finding.

(xii) The essential facts of the case were disclosed to all interested parties in the form of confidential and general disclosures. Comments of the interested parties on the disclosure statement, to the extent they are relevant and supported by evidence, have been considered by the Authority.

(xiii) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties. \*\*\*\* in this notification represents

information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.

**C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND “LIKE” ARTICLE.**

6. The product under consideration in the present investigation, as defined in the original investigation, is Flexible slabstock polyol, a polymer, originating in or exported from the subject countries. The subject product is a clear viscous liquid of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible slabstock polyol is transported in tankers or stored in steel drums. It is classified under the category “Plastics and articles thereof” in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907.20 as per International Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.

7. This being a sunset review investigation, the scope of the investigation is limited to the product already identified in the original investigation. No interested party has extended any argument on the issue of the product under consideration and like article. The subject goods produced by domestic industry are used interchangeably with those imported from the subject countries. Therefore, the Authority holds that the two are “like articles” within the meaning of the Rules.

**D. STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

8. The sunset review has been initiated on the basis of a duly substantiated request submitted by M/s. Manali Petrochemicals, Chennai, the sole domestic producer, on behalf of the domestic industry. Therefore, the Authority holds that M/s Manali Petrochemicals constitute the domestic industry for the purpose of the current investigation.

**E. VIEWS OF THE INTERESTED PARTIES**

**a) On initiation**

9. The European Commission had urged the termination of the investigation without extending the measures to exports from the EU, stating that the measures under review were part of 27 measures subject to DSU consultations as being in breach of WTO Rules, and a dispute settlement panel had not been requested owing to a subsequent mutual understanding with India. While most measures were no longer in place, the EC had expected the others to lapse and was disappointed at the initiation, which implied that measures not legally warranted in the first place were now being reviewed and could possibly be extended. The EC has further stated that the initiation notice confirmed removal of injury to the domestic industry and the request for review did not contain convincing evidence of likely recurrence of injury, being prompted by an assumption of



surge in imports if measures were repealed. However, the Authority had noted that the domestic industry had approached it within the prescribed legal framework and regions other than the EU were involved and therefore, allowed the investigations to proceed.

10. In its submissions at the public hearing, M/s Shell Eastern Petroleum Pte Ltd (hereinafter referred to as SEPL) from Singapore objected to the initiation of the review on the ground that the domestic industry has not been able to establish a case for review and had enjoyed the protection of safeguard and anti-dumping duties for long. That the present review was discriminatory, unlawfully initiated, beyond the scope of the Customs Tariff Act (hereinafter referred to as CT Act) and should be terminated *in limine*. In response, the domestic industry held that no interested party had filed comments to initiation within the stipulated period and therefore, could not be allowed to raise objections later to impede the investigation. This technical objection was contested by the importer, M/s DP Foam (hereinafter referred to as DPF), as neither the CT Act nor the AD Rules impose any limitation on submissions by interested parties. Besides, no provision of the AD law prevents a co-operating party from objecting or making submissions to the petition filed. In addition, SEPL has submitted that if it had been intended that legal submissions in an AD investigation should be made by a particular date, the Authority would have provided a record closing date, which was not the procedure or practise followed in India. The Authority noted that the responses by all parties had been made within the stipulated time frame.

**b) On claim of excessive confidentiality by the exporters:**

11. The domestic industry has submitted that the exporters from the subject countries have failed to provide meaningful summary of the response to exporter's questionnaire, the non-confidential version being incomplete & deficient and have claimed excessive confidentiality without justification. Hence, they may be considered non-cooperative by denial of individual treatment. Further, if the request for confidentiality was unwarranted and the supplier unwilling to make the information public or authorize its disclosure in generalized or summary form, such information could be disregarded. SEPL has averred that they had fully co-operated with the Authority in the said investigation and that it was the domestic industry that turned the investigation into a fishing expedition by not furnishing the requisite information at the initiation stage itself. Besides, there would be no means for the domestic industry to be privy to the contents of the confidential version of the responses as the data furnished was fiscal in nature and there was a distinction between transparency in investigation procedure and confidentiality of sensitive data.

12. The Authority however, noted that BASF South-East Asia Pte Ltd (hereinafter referred to as BSEA) subsequently provided the non-confidential versions of the lacunae in the questionnaire response indicated by the domestic industry in their written submissions which SEPL did not do, claiming that they had submitted all the required responses.

**c) On production process**

13. SEPL has stated that there are broadly three processes – (i) SMPO, (ii) chlorohydrin and (iii) MTBE- of producing PO and FSP, each with a different set of production and economic dynamics. Its manufacturing cost centre, Shell Chemicals Seraya Pte Ltd (hereinafter referred to as SCSL) with a nameplate capacity of 160 KT of PO, among others, uses the SMPO process which is the proprietary process of SEPL, while the domestic industry with a total installed capacity of only 24 KT PO, uses the chlorohydrin route process, the advantages of the SMPO process over the chlorohydrin process are a more efficient conversion process, higher yields and less waste products requiring less stringent treatment. Moreover, SMPO investments are often integrated with crackers to optimize product logistics. The domestic industry has argued that SEPL was trying to mislead the Authority by stating that the SMPO process was used for manufacturing PO and FSP whereas the SMPO process was only for producing PO, not FSP, the manufacturing process for which was the same all over the world. SEPL has refuted the charge of attempting to mislead the Authority in its post-disclosure comments.

**d) On relative advantages**

14. SEPL has stated that their feedstock was petrochemicals and petrochemical plants in Singapore were concentrated on Jurong Island, which collectively represent an integrated, pipeline connected series of plants, assets and utilities. SEPL shared common facilities with various units on a time and effort or actual use basis, which reduced the unit cost of production and has its own jetties capable of directly loading the subject goods into ships from the island itself. Therefore, SEPL enjoyed considerable economies of scale, procurement, and logistics, pipeline integration, process infrastructure, and technology and also uses different feedstock/ raw material. The domestic industry has charged SEPL with knowingly and deliberately using SEPL and SCSL interchangeably to confuse the Authority to detract attention from the main issues, viz., that there was no response of SCSL on record as on date and they cannot state the advantages enjoyed, if any, by SCSL as of SEPL. In any case, these advantages would be duly reflected in their cost of production. SEPL has refuted these charges post-disclosure.

**e) On questionnaire response**

15. The domestic industry has held that in the response to the exporter's questionnaire,

(i) SEPL has indicated that the raw material - propylene oxide (PO) - used in FSP production was sourced from SCSL & Shell Seraya Pioneer Pte Ltd (SSPL), both 100% subsidiaries; further, though a separate legal entity, SCSL was treated as a fully integrated cost centre. The domestic industry has argued that it implied that the PO purchased from SCSL was taken at cost for determining cost of the subject good, instead of the arm's length or market price; similarly for ethylene oxide purchased from a related company. AD laws do not provide for considering costs of another legal entity for the "ordinary course of trade" test.

(ii) SEPL has evaded the question on the basis of pricing of inputs purchased from related supplier and evidence of (a) such price being representative of fair market price; (b) purchase prices from independent parties for identical or comparable input,

(iii) SEPL has kept confidential without reason details of financial/ contractual links and joint ventures with other companies for the product, trading arrangements on goods affecting purchase price, investments, financial accounting system and change in accounting methods over the last three financial years, useful life for production equipment, depreciation, cost centres., etc: Further, SEPL has not provided details on product coding system, inclusion of any other consideration/ relationship/ reimbursement, or compensation etc. in prices, interest costs charged to the product, accounting for by-products sold, difference in factory cost for the domestic and export markets.

(iv) Regarding captive or purchased inputs, SEPL referred to PO produced in-house by SCSL and sourced from SSPL, instead of details of its own inputs, to mislead the Authority.

(v) SEPL and BSEA have not answered the query on change in the structure of the company in the last three years including the POI or provided details of related companies engaged in the production and sales of subject goods.

(vi) BSEA has kept confidential the tolling agreement between the exporter and Seraya, names of contact persons, details of and nature of relationship with related companies supplying inputs, catalogue and brochures, flow diagram, chart, financial and cost accounting systems and change in accounting methods in last three years, useful life of production equipment, depreciation, stock valuation, etc.

(vii) In the exporter questionnaire, BSEA has often referred to SCSL's response, which has not been filed and hence, normal value should be constructed.

(viii) BSEA has not clarified paying taxes / duties on inputs purchased, transportation cost incurred on inputs, basis of pricing of captive raw material and purchased from related parties, citing inability as a tolling customer, nor has provided copies of trading, profit & loss account, balance sheet for POI & previous years.

(ix) Appendix 3 of BSEA's questionnaire response shows FSP price higher in the domestic market and to other countries compared to prices to India, clearly depicting that the goods have been dumped in India during POI and dumping would continue in case the duties are discontinued.

16. The Authority has taken note of these submissions and examined them at appropriate places in this finding, taking cognizance also of BSEA's replies to the queries pertaining to them.

**f) On R&D expenses**

17. SEPL has charged that the domestic industry's total expenditure on Research and Development as percentage of total turnover was merely 0.18% as evident from their Annual Report, 2005-06 and they were not even attempting to increase competitiveness by investing in better technology, infrastructure etc., instead relying upon the protection of AD duty being levied on foreign competitors. The domestic industry has stated that the level of expenses on R & D was an irrelevant factor in an AD investigation and a bare statement had been made without providing any material on record on its relevance factor. Besides, the technology adopted by the domestic industry for the manufacture of FSP was comparable with any other producer in the world.

**F. CONTINUATION OF DUMPING.**

18. Under Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act 1975,

“Normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-

a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

19. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). Only two exporters from Singapore responded.

## **F.1 Normal value determination for EU, Japan, Singapore and USA**

### **F1.1 Views of the interested parties**

20. The domestic industry has constructed the normal value based on the cost of production in India, including selling, general and administrative expenses (SGA) and reasonable profit, citing inability to obtain documentary evidence or reliable information on home market prices of the product in the subject countries and the non-availability of such information in the public domain. They have claimed that dumping has not ceased from the sources on which anti-dumping duties were imposed initially and if the duties were revoked, the impact of dumping would be more serious. That the exporters from the subject countries had indulged in dumping in the years prior to the POI, without any change in their pricing behaviour and would continue to do so in future also.

21. SEPL has denied the allegation of dumping, stating that it exported significant quantities of the subject product in the Asia-Pacific and other regions including India and also sold in the domestic market; that imports at lower prices did not per se indicate dumping; that their questionnaire response substantiated that FSP production cost was significantly lower than the constructed value alleged of US \$ 2174 PMT due to SCSL's world class plant which has superior technology and higher scale economies with seven times higher nameplate capacity compared to the domestic industry; that the Authority must take cognizance of their data; and calculate normal value based on the domestic sales price and the manufacturing costs, not constructed normal value.

22. Like-wise, BSEA has claimed that their average CIF price to India was above the average ICIS price during the POI and the average CIF price reported in the petition filed by the domestic industry. The domestic industry has discounted this claim, stating that BSEA has not provided any supporting evidence that its prices were above the average ICIS price and that the export price was to be compared with the domestic prices of the exporter to arrive at the dumping margin, not prices reported elsewhere. Besides, for the determination of normal value, the response of the manufacturer producing the subject goods ought to have been filed with the Authority but there is no response of SCSL (reported to be the producer of FSP for BSEA). In such a case, normal value of the exporter cannot be determined, but has to be constructed.

23. BSEA has further stated that the landed value for the subject goods was above the reference price fixed and there was no reason why exporters would apply lower prices if the existing measures were withdrawn considering they have managed to sustain much higher prices before, enclosing an EC case to support their contention. The domestic industry has argued that the landed value for the subject goods has increased due to the direct increase in the raw material prices and even so, was still lower than the increase in the total cost and the imports are still coming at dumped prices. Further, the facts of the EC case were different and the comparison did not hold good.

24. DPF has submitted that there was no basis to assume that the pricing behaviour of the exporters have not changed when there was a significant difference between the

landed value of imports and the reference price during the POI. If the allegation of the domestic industry were true, the exporters would be exporting at the reference price or below to ensure that domestic industry was forced to lower their prices, which was clearly not the case. DPF has further submitted that if exporters from the subject countries failed to cooperate in the sunset review investigation and the Authority records its findings on best judgment assessment, the Authority ought to adopt the lower of the sale price of the subject goods in the exporting country, the export price of the subject goods to third countries, and the constructed normal value in determining the normal value, because of the monopolistic nature of the domestic industry. The domestic industry has debunked this submission, stating that the legal justification for taking such an approach for the determination of normal value has not been given.

25. The importer has further said that the demand for the subject goods during the POI was about 30,000 MT, increasing at approximately 15% per annum. Even though the domestic industry licensed capacity was 37,000 MT, its installed capacity was 14,000 MT, of which it also produced other polyols. Hence, it did not have the capacity to meet the demand and even at 100% capacity utilization, would not be able to meet even 50% of the demand. Besides, the domestic industry has failed to increase its capacity proportionate to increase in demand, seeking to use its monopolistic status and safeguard & AD duties to earn undue profits at the expense of the small-scale industries (SSI) in the country, which are the end-users of the subject goods. Thus, the shortfall in demand has to be met by imports. If AD duties are very high due to a high dumping margin, the SSIs that use the subject goods as raw material would suffer grave injury.

26. The domestic industry has responded that the current annual capacity of their polyol plant of 15500 MT could be enhanced to 23000 MT per annum by process modifications if assured of a reasonable selling price for their products. Presently they could not even fully utilize current capacity. Besides, there was no legal reason to suggest that AD duties could not be imposed if the domestic industry cannot fulfill the entire demand in the country. FSP imports from subject countries have increased because of severe dumping, not due to increase in domestic demand. If the imports had been at non-dumped prices, the industry also would have realized fair prices for the subject goods.

## **F.2 Examination by the Authority**

27. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties and the issues have been addressed in appropriate places in the findings.

Section 9A (5) of the CT Act provides that the Authority, in a sunset review, is required to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Hence, the issues before the Authority are to examine

- ❖ Whether dumping is likely to continue or recur, if definitive duties are removed or allowed to expire;

- ❖ Whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur, if definitive duties are allowed to expire or are removed.

The issues have been examined in the ensuing paragraphs.

### **F.2.1 Normal Value & Export Price**

28. The Authority noted that no exporter from the subject countries except SEPL and BSEA from Singapore provided information or co-operated in the investigation to enable the determination of normal value and export price of the subject goods from the subject countries. Therefore, the Authority has determined that the dumping margin for the non-co-operating exporters from the subject countries on the basis of facts available in terms of Rule 6 (8) of AD Rules read with Article 6.8 of the Agreement. The average exchange rate adopted for the purpose of this investigation for the POI was Rs 44.62 per \$.

#### **F.2.1.1 Normal value for USA**

29. The Authority has constructed the normal value based on the cost of production, conversion costs and selling, general & administrative expenses of the domestic industry in India together with a reasonable margin of profit. The normal value so constructed is Rs. \*\*\* or \$ \*\*\* per MT.

#### **F.2.1.2 Normal value for Japan**

30. The Authority notes that as per the transaction-wise data from DGCIS, there were no imports from Japan in the POI and in the base year, while in the interim years, the imports were de-minimis. Therefore, no dumping margin has been computed for Japan.

#### **F.2.1.3 Normal value for European Union**

31. The Authority has constructed the normal value based on the cost of production, conversion costs and selling, general & administrative expenses of the domestic industry in India together with a reasonable margin of profit. The constructed normal value is Rs. \*\*\* or \$ \*\*\* per MT.

#### **F.2.1.4 Normal value for Singapore**

32. The data submitted by co-operating exporters to this investigation were verified in accordance with the Rules and reports of such verification carried out by the Authority were made available to the exporters for their comments. The dumping margins in respect of these exporters have been worked out based on the verified data taking into account the comments of the exporters to the verification reports to the extent they are relevant and valid.

33. The Authority notes that the Hon'ble Supreme Court of India, in the Civil Appeal No. 1294 of 2001, M/s RIL Vs Designated Authority & Others, has held that normal value is not exporter-specific but exporting country-specific.

34. In its post disclosure comments, the domestic industry has submitted that the computation of a single weighted average normal value is not for cooperating exporters and that individual normal value is required to be determined for each such exporter, which is contrary to the Supreme Court order in the case. The Authority notes that due to different conditions of sales in the domestic market by the cooperating exporters, the weighted average normal value in the country of exports gives a significantly distorted result. However, in pursuance of the Supreme Court Judgment in the afore mentioned case, the normal value of the subject goods for the subject countries have been determined, first for the individual co-operating exporters and then a single weighted average normal value has been worked out for the product under consideration for the exporting country as a whole based on the normal values determined for the co-operating exporters

#### **Salient features of the exporter verification**

##### **A. SEPL**

35. SEPL is a private limited company incorporated and registered in Singapore and a manufacturer of the subject product and other products. SEPL's FSP plants are located in Singapore and operated by SCSL, SEPL's production facility, which was originally established as a joint venture between Shell & Mitsubishi and later transformed into a 100% subsidiary. Although a separate legal entity, SCSL is treated as a fully integrated cost centre within the statutory accounts and as a single tax entity with SEPL. It is a manufacturing cost centre that produces among others, PO, the whole of which, sold at cost to SEPL, is used in the production of FSP and other products. The name plate capacities for PO are \*\*\*, and for FSP \*\*\* per annum.

36. SSPL is another 100% subsidiary of SEPL established in 2002, which is principally involved in sale of PO. It is also a separate legal entity and sells PO to other customers. In addition, in a 50% partnership with BASF, SSPL has constituted another separate legal entity named ELLBA, having annual production of \*\*\* of PO. ELLBA is treated as a cost centre, the principal activity consisting of production and sale of PO to its shareholders at cost.

37. SEPL purchases and imports propylene feed-stock from different sources, converting it into propylene oxide, the purchase price in the POI ranging between US\$ \*\*\* - \$ \*\*\* PMT. The PO consumed is from SCSL, SSPL and BSEA, the main supplies being from SCSL and SSPL and the top-up supplies from BSEA. SEPL has a tolling arrangement with BSEA, whereby PO received from the latter is converted into polyols and supplied back to BSEA from its ELLBA plant. Hence, the weighted average price of PO has been charged to cost of production. In its various submissions, the domestic industry has reiterated that the PO should be taken at the market price and not at cost. As



SCSL is a fully integrated cost centre of SEPL, there is no rationale to charge PO at market price

38. FSP is produced by SEPL by reaction of PO and depending on the grade, EO with Glycerin as an initiator. The main raw material, PO, represents about 90% by weight of the subject product, EO and glycerine, jointly constituting about 10% of weight. EO is supplied via pipeline by Ethylene Glycol Singapore (EGS), a joint venture of SEPL, while glycerine is supplied in bulk shipments from Malaysia, with minimal logistics costs. SEPL also produces three other grades of polyols, though primary production is of the subject product, which, among others, is sold in domestic and export markets including India. The cost of production was verified as US\$ \*\*\*.

39. Transaction wise details of sales of Polyol SC 56-02 in the domestic market showed that these sales were \*\*\* MT. Sales to BSEA, kept outside the ambit of domestic transactions, being under a tolling agreement, were \*\*\* MT during the POI. The sales have been at varying prices. Sales to Bayer, which was neither a subsidiary nor a related company, are at comparatively lower rates as a comparatively larger buyer. For other customers, prices charged depended on the market. All domestic sales of the company were above cost of production and average selling price of these transactions comes to US\$ \*\*\* PMT. The adjustments on domestic sales claimed towards inland freight, storage, notional credit cost, surveyor and mooring fees have been allowed after verification. Net of adjustments, the weighted average ex factory normal value comes to US\$ \*\*\* PMT.

Domestic sales	Unit Sale price	Adjustments	Ex-factory NV
In MT	\$ PMT	\$ PMT	\$ PMT
***	***	***	***

#### B. BSEA

40. BSEA is a part of the BASF group of companies, with the global headquarters at Brussels coordinating regional business units, a global R & D centre at Ludwigshafen, Asian region marketing & technology headquarters at Hong Kong and local sales offices in each country. The cost-sharing arrangements are handled by the global entities. BSEA as a manufacturing company covers the finance and supply chain management functions.

41. BSEA did not have its own FSP manufacturing facility. Propylene is purchased by ELLBA which is a 50-50 joint venture of Shell & BASF and converted into PO. The suppliers bore no legal relation to BASF and propylene is purchased from local as well as overseas suppliers at prevailing market conditions partly on spot basis. BSEA had signed a tolling arrangement with SCSL effective from 2002, whereby BSEA would supply PO to SCSL, which would produce FSP and invoice back the same to BSEA. BSEA could source an increasing amount of FSP, till a final plateau of annual volume was reached, subject to a tolling fee, covering all actual cost and an appropriate rate of return. The arrangement could be terminated 7 years after commencement of the first FSP supply. BSEA sells this finished product as per its own marketing arrangements and under a

different brand name. Both SEPL and BSEA are two separate legal entities and have nothing in common except this arrangement.

42. Analysis of domestic sales showed that BSEA has sold \*\*\* MT in Singapore at profit and exported \*\*\* MT to India during the POI, exports to India commencing from Feb 2004 in drums. The domestic sales represent approximately \*\*\*% of their exports to India. BSEA utilised the services of a warehousing company, and paid a fee for their services.

43. Thus, BSEA's cost of production reflects the cost of PO, tolling fees for converting PO to FSP, cost of variable and fixed manufacturing overheads, return on investment, and the cost of shipping. SGA expenses which included the percentage share of their marketing offices at Hong Kong and administrative office at Brussels, were added. The ex-factory normal value, after adjusting for inland freight, packing cost and lifting fees, is as below.

Domestic sales	Unit Sale price	Adjustments	Ex-factory NV
In MT	\$ PMT	\$ PMT	\$ PMT
***	***	***	***

44. In pursuance of the apex court's ruling in CA No. 1294/2001 that normal value is exporting country-specific, a single weighted average normal value for the subject product for Singapore as a whole was worked out, based on the normal values of the cooperating exporters. This normal value has been compared with the export price for the individual exporters to determine individual dumping margins of the exporters. The normal value so determined is \$ \*\*\* or Rs. \*\*\* per MT.

	SEPL	BSEA	Weighted average
Normal Value	***	***	***

### F.3 Export Price

45. For the non-cooperating exporters from the subject countries, the Authority has taken the official price for calculation of dumping margin and price undercutting. A weighted average export price to India has been determined for the subject product. Adjustments like freight, insurance, commission and handling expenses have been conservatively allowed. In its post-disclosure comments, the domestic industry has submitted that for non-cooperating exporters, the lowest export price and not the weighted average export price ought to be taken by the Authority. However, for non-cooperating countries, the Authority has adopted as a consistent practice, the weighted average export price, to avoid zeroing of transactions.

#### F.3.1 Export Price for USA

46. The weighted average export price has been taken as US \*\*\* per MT and after adjustments, the ex-factory export price comes to \$ \*\*\* per MT.

**F.3.2 Export Price for European Union**

47. The weighted average export price has been taken as US \$ \*\*\* per MT and after adjustments, the ex-factory export price comes to \$ \*\*\* per MT.

**F.3.3 Export Price for Singapore**

48. The Authority had verified the data on exports sales of the co-operating exporters from Singapore and has determined the export price as below:

**A. SEPL**

49. SEPL had exported FSP to several countries in the POI. Third country exports (excluding India) constituted \*\*\* MT in the POI, while those to India were \*\*\* MT, or 3.3% of total exports. \*\*\* MT were exported by bulk containers through road/sea, \*\*\* MT by bulk tankers and \*\*\* MT by packed containers through road & sea. The adjustments as per the different modes of transportation, rebate/ commission, notional credit cost, inland cross harbour, outbound and overseas freight, charges towards shipping, insurance, port, storage and nitrogen inerting, surveyor and mooring fees and packing costs were checked. The per unit ex-factory export price was calculated for different modes and the weighted average export price after adjustment works out to US\$ \*\*\* per MT at the ex-factory level.

Particulars	\$ PMT
Export Price	***
Less adjustments	***
Ex-factory Export Price	***

**B. BSEA**

50. BSEA, being a trader in the subject goods, the unit export price was adjusted for packing charges, lifting fees, freight and inland transport the per unit ex-factory price calculation is given as below:

	\$ PMT
Export Price	***
Less adjustments	***
Ex-factory Price	***

**C. Other exporters from Singapore**

51. For the other exporters, the lowest export price of SEPL, duly adjusted was taken as the ex-factory export price.

#### F.4 Dumping margin

##### F.4.1 Dumping margin for USA

52. The Authority has worked out the dumping margin by making a comparison between the normal value and export prices at ex-factory level, based on the constructed normal value and the lowest export price determined for the product. The dumping margin is \$ \*\*\* per MT or 18.96 %, which is significant.

##### F.4.2 Dumping margin for European Union

53. The Authority has worked out the dumping margin by making a comparison between the normal value and export prices at ex-factory level, based on the constructed normal value and the lowest export price determined for the product. The dumping margin is \$ \*\*\* per MT or 0.40 %.

##### F.4.3 Dumping margin for Singapore

54. The Authority has worked out the dumping margin by making a comparison between the weighted average normal value and export prices at ex-factory level. For the co-operating exporters, the dumping margin is negative. The Authority noted that the negative dumping margin of BSEA resulted from the Court's ruling that normal value should be exporting country-specific, not exporter-specific. For others, the dumping margin has been determined as the difference between the weighted average normal value and the lowest export price of the co-operating exporter after adjustments. The dumping margin is thus \$ \*\*\* per MT or 0.45%.

#### F.5 Dumping margin : Summary

Product	Country	Exporter	Dumping margin	Dumping margin %
			\$ PMT	
Flexible slabstock polyol of MW 3000-4000	USA	All	***	18.96%
	Japan		No exports in the POI	
	Singapore	SEPL	***	-5.39%
		BSEA	***	-6.19%
		Others	***	0.45%
	EU	All	***	0.40%

55. The dumping margin from USA is significant. Dumping margins during the POI for Singapore and the EU were found to be either negative or marginal. There is no export from Japan in the POI and therefore, current dumping margin from this country could not be determined. However, the Authority notes that in a sunset review, current dumping margin is not a material fact and what is required to be examined is the likelihood of recurrence in the event of no dumping during the investigation period.

**G. INJURY AND CAUSAL LINK: CONTINUATION OF INJURY**

56. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

Determination of Injury:

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India.

(2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules.....”

57. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. Annexure-II (ii) of the Rules provides as under:-

(ii). “While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India With regard to the effect of the dumped imports on prices ...the designated authority shall consider whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, to a significant degree.

Annexure II to the Rules further provide that

“(iv). The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

**G.1 Views of interested parties**

58. The domestic industry has argued in a sunset review, injury analysis is required to be made by analysing the likely impact on the domestic industry if anti dumping duties

are not extended. The situation of the domestic industry had improved after imposition of AD duty indicating that the duties have been effective but the effect was not to the desired effect as the exporters have continued to indulge in injurious dumping and the injury to the industry would continue if duties are not extended.

59. The other interested parties have argued that the domestic industry had improved its performance and suffered no injury at the moment and injury, if any, was due to their own inefficiencies and cannot be attributed to the imports from these sources. According to the petition itself, many of the injury indices indicated improvement or had a marginal decline, leading *a priori* to the conclusion that it was not dumping that caused injury to the domestic industry. The domestic industry has argued that the focus in a sunset review was on the likelihood of dumping and injury and hence even if there is no dumping, it was of no consequence for the 'likelihood' test.

## **G.2 Examination by the Authority**

60. The Authority has taken note of the arguments raised by the various parties in their submissions and the issue of likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry has been examined in the light of these arguments made before the Authority.

61. The Authority noted that this was a sunset review of the measure already in force and examined the issue of cumulative assessment of injury to the domestic industry on account of simultaneous dumping from the subject countries, in terms of Annexure II (iii) of the AD Rules and holds that the conditions specified in the said Rules are satisfied in this case for cumulative assessment, except for imports from Japan.

62. For the purpose of injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports on the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability. To examine the existence of injury and causal links between dumping and injury, if any, since a positive dumping margin has been established for the exports from the subject countries, the entire exports has been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal link examination.

### **A. Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry**

#### **Import statistics**

63. Transaction-wise data from DGCI&S show that the subject product imports has been reported under customs classifications 39072000, 39072010 and 39072090. Since the product description is only indicative, all imports of subject goods irrespective of their classification have been included for the purpose of determination of volume, value and average import price. As the exporters from Singapore have provided data on their exports to India, which are higher in volume and value as compared to DGCIS data for the POI, this data has been adopted for the POI and shown in the column POI.<sup>2</sup> The bulk of the product imports are from the subject countries at present, as below:-

<b>FSP Imports</b>	<b>2002-03</b>	<b>2003-04</b>	<b>2004-05</b>	<b>POI<sup>1</sup></b>	<b>POI<sup>2</sup></b>
Total product imports					
Qty (MT)	9531.36	10491.80	12992.14	13795.06	15249.18
Value (Rs lacs)	4190.60	5514.14	9086.87	11377.88	12262.62
Price/MT	43966	52557	69941	(82478)	80415
Imports from subject countries					
Qty (MT)	586.62	3258.96	6101.00	9622.13	11076.25
Value (Rs lacs)	346.38	1845.03	4163.56	7945.08	8829.83
Price/MT	59048	56614	68244	82571	79719
Share in total imports	6.15	31.06	46.96	(69.75)	72.64
Imports from other countries					
Qty (MT)	8946.01	7232.84	6891.14	4172.93	
Value (Rs lacs)	3844.78	3669.11	4923.31	3432.80	
Price/MT	42978	50729	71444	82264	

Note: POI<sup>1</sup>: DGCIS data; POI<sup>2</sup>: exporters data.

64. The Authority noted that from a mere 6% of total product imports in 2002-03, the subject countries' imports increased to 31%, 47% and 73% respectively in the years thereafter, registering an extremely rapid growth. Anti-dumping duty is in place on imports from countries not included in the scope of the current investigation, viz., Brazil, Korea, China PR and Chinese Taipei. The share of these countries including those not dumping was 94% of total imports in 2002-03 and declined to 27% in the POI. As per DGCIS data, the average CIF price of imports from other countries was lower than those from the subject countries by a considerable margin in the first two years of the injury period and was higher only in 2004-05. In the POI, though the rate of imports from other countries were lower compared to subject countries, the margin of difference was insignificant. On the other hand, the data based on exporters' information showed that in the POI, the unit rate was lower in the case of subject country imports.

65. Subject country imports have been de-segregated and individual country details are as below:

<b>Imports</b>	<b>2002-03</b>	<b>2003-04</b>	<b>2004-05</b>	<b>POI<sup>1</sup></b>	<b>POI<sup>2</sup></b>
Imports from EU					
Qty (MT)	390.36	420.00	332.43	1418.17	No response
Value (Rs lacs)	256.70	267.12	267.79	1175.23	
Price/MT	65759	63600	80556	82870	
Share in dumped imports	66.54	12.89	5.45		12.80
Share in total imports	4.10	4.00	2.56		9.30
Imports from Japan					
Qty (MT)		5.82	32.00		No response
Value (Rs lacs)		3.31	20.53		
Price/MT		56816	64161		
Share in dumped imports		0.18	0.52		

Share in total imports		0.06	0.25		
Imports from Singapore					
Qty (MT)	196.26	2781.14	2159.47	4434.00	5888.12
Value (Rs lacs)	89.69	1542.96	1441.38	3696.34	4581.08
Price/MT	45699	55479	66747	83364	77802
Share in dumped imports	33.46	85.34	35.40		53.16
Share in total imports	2.06	26.51	16.62		38.61
Imports from USA					
Qty (MT)		52.00	3577.10	3769.96	No response
Value (Rs lacs)		31.64	2433.85	3073.51	
Price/MT		60848	68040	81526	
Share in dumped imports		1.60	58.63		34.04
Share in total imports		0.50	27.53		24.72

Note: POI<sup>1</sup>: DGCIS data; POI<sup>2</sup>: exporters data.

66. The Authority noted the following:

- ❖ The share of EU which was the highest in the base year at 66.5% of total subject country imports fell to 6% in 2004-05 but rose to about 13% in the POI. As percentage of total imports, EU imports which were 4.1% in 2002-03, dropped to 2.56% in 2004-05 and grew again to 9.30% in the POI.
- ❖ Imports from Japan were nil in 2002-03 and the POI and insignificant in the interim.
- ❖ Imports from Singapore had constituted a high percentage of 85% in 2003-04, but in the POI was 53%. Its share in total imports increased 10-fold from the base year in 2003-04, fell to 16% in 2004-05 and increased to 39% in the POI.
- ❖ Imports from USA - merely 1.6% in 2003-04 - registered an increase to 59% in 2004-05 and in the POI, was 34% of dumped imports. As percentage of total imports, USA constituted about 25% in the POI.

67. In the following analysis, DGCIS transaction data is utilised to assess volume of imports and domestic demand except for the POI, where exporters' data has been used. However, imports from Japan are excluded.

a) **Import volumes**

68. With regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

69. For the calculation of the domestic consumption/demand of the subject goods, the Authority added the sales volume of the domestic industry to the total imports into India.

Parameter (in MT)	2002-03	2003-04	2004-05	POI <sup>1</sup>
Total Imports	9531	10492	12992	12199



Indexed	100	110	136	128
Imports from subject countries	587	3253	6069	8861
Indexed	100	555	1039	1510
Sales of Domestic industry	***	***	***	***
Indexed	100	124	114	125
Domestic demand	***	***	***	***
Indexed	100	116	126	126
Domestic production	***	***	***	***

Note: : Annualised on pro rata basis

Source: Domestic industry, DGCIS.

70. The Authority noted that domestic demand (indexed) grew by 126 over the injury period, compared to 125 in the domestic sales and of 128 in total imports, while subject countries imports recorded a 14-fold rise over the same period. Further, while total imports dipped in the POI compared to 2004-05, domestic demand remained stable in the last two years of the injury period and subject country imports maintained a consistent uptrend all along. Domestic sales fell in 2004-05, but recaptured the lost momentum in the POI, even though demand remained at the same level in the two years.

**b) Actual and potential effect on sales and market share of the domestic industry:**

<i>Percentage share</i>	<i>2002-03</i>	<i>2003-04</i>	<i>2004-05</i>	<i>POI<sup>1</sup></i>
<b>In domestic demand</b>				
a) Subject countries imports	***	***	***	***
Indexed	100	476	822	1194
b) other imports	***	***	***	***
Indexed	100	69	62	30
c) total imports	***	***	***	***
Indexed	100	95	108	101
d) domestic industry	***	***	***	***
Indexed	100	106	90	99
Dumped imports/DI production (%)	7.44	32.34	59.32	89.13

Note: : Annualised on pro rata basis

Source: Domestic industry, DGCI&S.

71. The Authority noted that the share of domestic industry in demand fell marginally by 0.6% from 46.7% in 2002-03 to about 46.1% in the POI, while total imports increased correspondingly. The market share of other country imports declined from 50% to 14.8% over the injury period, which decline was absorbed by imports from the subject countries in total. Consequently, though the volume of the subject country imports increased manifold from the base year, as a percentage of domestic demand, the increase in "dumped imports" crowded out other country imports and not so much the domestic industry.

**c) Actual and potential effects on capacity, output and capacity utilization of the domestic industry**

72. The performance of the domestic industry has been examined with reference to its capacity, output, capacity utilization and impact of dumped imports on these parameters, if any.

<i>Parameter</i>	<i>2002-03</i>	<i>2003-04</i>	<i>2004-05</i>	<i>POI<sup>1</sup></i>
Capacity	11250	11250	11250	11250
Production	***	***	***	***
Indexed	100	128	130	126
Capacity Utilization (%)	***	***	***	***
Indexed	100	128	130	126
Domestic Demand (MT)	***	***	***	***
Indexed	100	116	126	126

Note: <sup>1</sup> : Annualised on pro rata basis

Source: Domestic industry.

73. The Authority noted that though the demand increased over the injury period, the domestic industry's installed capacity remained unaltered. Capacity utilisation (indexed) declined in the POI marginally by 4 after increasing to 130 in 2004-05, reflecting the trend in production. Despite the decline, capacity utilisation during the injury period rose by 18% from the base year. The Authority noted the domestic production was about half the domestic demand so that imports are necessary to meet the shortfall in supply.

**B. Price effect of dumped imports**

74. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

75. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realisation (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject countries to examine whether there has been significant price under-cutting or under-selling by the dumped imports compared with the price of the like product in India or whether such imports have depressed the prices or prevented price increases that otherwise would have occurred to a significant degree.

76. Price under-cutting has been determined by comparing the landed value of dumped imports, with the weighted average ex-factory NSR of the domestic industry, where the rebates, discounts, commissions offered and the excise duties paid have been

excluded. For price under-selling analysis, the landed value of dumped imports was compared with the NIP of the subject goods, determined by taking into account verified cost and SGA expenses of the industry, together with a reasonable profit margin. To examine the price suppression and depression effects, the trend of NSR of the domestic industry has been compared with the cost of sales.

<i>Parameter (Rs. /MT)</i>	<i>2002-03</i>	<i>2003-04</i>	<i>2004-05</i>	<i>POI</i>
Landed Price	77530	68616	82738	92191
Indexed	100	89	107	119
Net Sales Realization of Domestic industry	***	***	***	***
Indexed	100	103	125	136
Cost of sales	***	***	***	***
Indexed	100	94	102	112
Price undercutting <sup>1</sup>	***	***	***	***
Price undercutting %	(15-20)%	(0-5)%	(0-5)%	(0-5)%
Non-Injurious Price				***
Price Underselling <sup>2</sup>				***
Price Underselling %				15-20%

Note: <sup>1</sup> NSR minus landed price of imports; <sup>2</sup> NIP minus landed value

Source: Domestic industry, DGCIS.

77. The Authority noted that on a cumulative basis, the indexed landed value of the subject country imports increased by 119 since 2002-03, and of NSR increased by 136. In each year of the investigation period, the landed value was higher than the NSR so that there is no price under-cutting. Post disclosure, the domestic industry has submitted that cumulative price undercutting analysis would be misleading and individual transactions were to be compared to the domestic price to judge price undercutting. However, the Authority noted that where imports from a number of countries are being simultaneously investigated, injury and causal link analyses are cumulatively assessed. Further, the Authority observed that except in 2003-04, the landed value has remained above the cost of sales, too and the trends in landed price and cost of sales of the domestic industry moved in the same direction. The NIP for the domestic industry has been determined at Rs \*\*\* per MT in the POI following the Supreme Court orders in CA No: 1294/ 2001 against a landed value of Rs. 92191, so that price under-selling is about 15-20%. The domestic industry's own figure of desirable selling price is Rs. \*\*\*. At this price, total price underselling would be only 0-3%. Further, the NSR (indexed) increased by 136 compared to 112 in the cost of sales, so that there is no price depression. Moreover though NSR was below cost of sales in the first two years of the injury period, there was a turn-around in the next two years so that there is no price suppression either.

### G.3 Examination of other injury factors

78. Some of the injury factors i.e. actual and potential decline capacity, production, capacity utilization, sales and market shares; were examined in the previous section along with actual and potential increase in volume of imports and it was noted that

- ❖ Production of the domestic industry decreased marginally in the POI after showing significant increase upto 2004-05.
- ❖ Capacity utilization fell by 3% in the POI.
- ❖ Sales of the domestic industry increased substantially in the POI, after a fall in 2004-05, though demand remained at the same level.

#### a) Actual and potential effects on profits

79. Profitability position of the domestic industry has been as under:

Parameter (in Rs. Lakhs)	2002-03	2003-04	2004-05	POI <sup>1</sup>
Cost of Sales of the DI	***	***	***	***
Sales realization of the DI	***	***	***	***
Profit/Loss (Rs./MT). <sup>2</sup>	***	***	***	***
Indexed	(100)	(31)	49	44
Profit/Loss on Domestic sales	***	***	***	***
Indexed	(100)	(39)	56	55
Interest	***	***	***	***
Indexed	100	94	62	10
PBIT	***	***	***	***
Indexed	(100)	(70)	175	182

Note: <sup>1</sup> Annualised on pro rata basis

<sup>2</sup> Sales Realization – Cost of Sales

Source: Domestic industry.

80. Though the cost of sales had been higher than the sales realization in the first two years of the injury period, 2004-05 saw a total turnaround in the performance of the domestic industry as reflected in rising profits.

#### b) Actual and potential effects on employment and wages

81. Employment level of the domestic industry has been as under:

Parameter	2002-03	2003-04	2004-05	POI <sup>1</sup>
Employees (No.)	***	***	***	***
Wages (Rs. Lakhs)	***	***	***	***
Indexed	100	102	106	110

Note: <sup>1</sup> : Annualised on pro rata basis

Source: Domestic industry.

The Authority noted that employment levels for the production of the subject product remained stable from 2002-03, but as the domestic industry was multi-product, employment levels per se may not be a conclusive indicator of injury. Wages, too, had increased in absolute terms. Therefore, this parameter is not a cause of injury to the domestic industry.

**c) Actual and potential effects on productivity**

82. The Authority noted that per employee productivity and sales increased till 2004-05. There was a marginal drop in productivity in the POI due to fall in production.

Parameter	2002-03	2003-04	2004-05	POI <sup>1</sup>
Productivity per Employee	***	***	***	***
Indexed	100	128	130	126
Sales per Employee (in Rs)	***	***	***	***
Indexed	100	120	142	170

Note: <sup>1</sup> : Annualised on pro rata basis

Source: Domestic industry.

**d) Actual and potential effects on cash flow, profits and return on investment**

83. As the domestic industry was a multi product company, examination of cash flow of the entire company may not be appropriate for the injury purposes. The Authority therefore, has examined cash profit situation of the domestic industry, capital employed and return on investments.

Parameter (in Rs. Lakhs)	2002-03	2003-04	2004-05	POI <sup>1</sup>
PBT	***	***	***	***
Indexed	(100)	(39)	56	55
Depreciation	***	***	***	***
Cash profit	***	***	***	***
Indexed	(100)	(27.9)	79	79
PBIT	***	***	***	***
Indexed	(100)	(70)	75	82
Capital Employed.	***	***	***	***
Indexed	100	96	92	79
Return on capital employed.(%)	***	***	***	***
Indexed	(100)	(31)	82	66

Note: <sup>1</sup> : Annualised on pro rata basis

Source: Domestic industry.

84. PBT, PBIT and cash profit improved from a position of loss to a situation of profits in 2004-05, which continued in the POI on a lesser scale. Likewise, return on capital employed (% , indexed) increased to 182 in 2004-05 and fell to 166 in the POI.

**e) Inventories**

85. Inventories position with the domestic industry has been as under:

Parameter (in MT)	2002-03	2003-04	2004-05	POI <sup>1</sup>
Average stock of inventory	***	***	***	***
Indexed	100	53	76	69
As % of sales	9.98	4.25	6.63	4.42

Note: <sup>1</sup> : Annualised on pro rata basis

Source: Domestic industry.

The Authority noted that average inventories have declined in the POI from the base year, both in absolute terms and as a percentage of sales.

**f) Ability to raise capital**

86. No evidence has been placed before the Authority to substantiate that the domestic industry has been facing problems with regards to the ability to raise capital.

**g) Growth**

87. The Authority notes that the growth in demand and the improvement in the performance of the domestic industry in terms of parameters, such as production, sales, profits, cash flow and return on investments from the base year to the POI.

**h) Degree of dumping margin**

88. The Authority notes that dumping margins from the subject countries, as an indicator of injury, are found to be significant in the case of USA only.

**G.4 Overall assessment**

89. The above analysis of the factors shows that despite the large volume of imports, the domestic industry has been able to maintain its share in the market and has not suffered injury over the relevant period since a majority of the parameters have shown improvement over the base year. There is no price undercutting, price suppression or price depression caused by subject country imports, but price underselling of 19% is seen.

## **G.5 Conclusions on injury**

90. The Authority noted that the volume effect of subject country imports has been relatively insignificant despite their increase in absolute terms and the price effect is restricted to price under-selling. Most parameters of the domestic industry do not reflect injury. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has not continued to suffer material injury.

## **H. CAUSAL LINK**

### **H.1 Views of interested parties**

91. The interested parties have claimed that a causal link had to exist between the material injury suffered by the Indian industry and dumped imports, which was completely absent from an analysis of the annual reports. The domestic industry has brushed aside this submission, stating that the annual reports of the company contained details for all the products as a whole, including the subject goods, so that any analysis based thereon would not be appropriate. Moreover, the causal link analysis was inconsequential in a sunset review as it had been established in the original investigation and was not required to be revisited.

92. On issues of non-attribution, the mandatory factors have been examined as follows:

- ❖ **Contraction in Demand:** - Demand for the subject goods has increased during the injury period and was stable in the POI.
- ❖ **Pattern of consumption:** - No significant change in the pattern of consumption has been alleged by any interested party.
- ❖ **Imports from other countries:** - Total subject product imports originating in countries other than the subject countries are declining, and they have been replaced by increasing imports from the subject country.
- ❖ **Conditions of competition:** - The goods are freely importable. The petitioner is the only producer of the subject goods.
- ❖ **Developments in technology:** - Interested parties have argued that the technology used by the domestic industry is old and inefficient, but the industry has refuted this, stating that the manufacturing technology was the same world over.
- ❖ **Others:** It has been alleged that the domestic industry suffers from location disadvantage, situated in a water-scarce region, whereas the subject product was water intensive.

### **H.2 Factors establishing causal link**

93. Examination of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance has not been affected due to dumped imports from the subject countries. Despite the increase in the volume of dumped imports by over 35% from the

base year, the market share of the domestic industry has declined only by 0.6% over the injury period. The increase in demand has been met by imports, but subject country imports have crowded out imports from other countries. There is no price under-cutting, but price under-selling is about 19%. Domestic sales have increased. Production and therefore, capacity utilization has declined marginally. Resultantly, profits, cash flow and return on investment of the domestic industry deteriorated fractionally in the POI after showing consistent improvement.

94. The above non-attribution analysis shows that the dumped imports from the subject countries, through their volume and price effects, have not caused significant injury to the domestic industry. The Authority, therefore, concludes that the injury caused to the domestic industry on account of imports from the subject countries is insignificant and immaterial.

## I. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

### I.1 Views of the interested parties

95. The domestic industry has requested the Authority to keep in mind the decision of the Supreme Court in *M/s RIL. Vs. DA* {2006 (202) E.L.T. 23 (S.C.)}, to determine the non-injurious price based on the transfer price (market value) of the captive inputs. DPF has held that on the contrary, the Authority ought to take into account the actual cost of the captive inputs, as reflected in the accounts of the domestic industry and verified by the Authority, in determining the NIP. That the reliance placed on the judgment was misplaced, as in holding that the market price of the inputs ought to be taken, the reasoning of the Court had been based on there being only one NIP determined for the domestic industry as a whole, and more than one constituent of the domestic industry, so that the others would be discriminated if transfer price was taken in the case of one constituent and cost of inputs for the other constituents producing the input captively. But as the petitioner was the sole manufacturer of the subject product, there could not be a case of discrimination among domestic industry constituents. Hence, the NIP had to be determined for the petitioner alone.

96. However, the Authority has determined the NIP taking into account the cost of production and other associated costs of the domestic industry during the POI as per the principles laid down in the aforesaid judgment, which works out to Rs \*\*\* per MT. The injury margin from the subject countries work out as below:

**Injury margin (Rs. / MT)**

Non-Injurious price		Landed value	Injury Margin	IM %
***	USA	94281	***	15-20%
	EU	95834	***	15-20%
	Singapore			
	SEPL	***	***	27-33%
	BSEA	***	***	27-33%
	Others	***	***	30-35%



	Japan	No exports in the POI		
	Total	92191	***	18-23%

## J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF DUMPING AND INJURY

97. Section 9A of the Act requires the Designated Authority, in an expiry review, to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

### J.1 Views of the interested parties

98. The domestic industry has claimed that the exporters have continued dumping even after the imposition of AD duty and in increasing volumes, which would accelerate if duties are revoked. They have claimed that the imports of the raw material, PO have been made at higher prices than the prices of the subject product, though PO requirement is about 90% of total FSP weight. FSP prices have been less by as much as 35% of the PO price, indicating severe dumping by the subject countries during the POI, which would continue and increase in future and injure the industry if duties are not extended. DGCI&S import data showed that the landed value to India for PO was higher than that of subject product, posing greater threat of continuance and recurrence of injury to the domestic industry.

99. In response, SEPL has submitted that the imports of raw materials are not a relevant consideration and even if so, there was no ready market in India as evident from the ICIS publication, which showed no price available for PO sales in India; that the PO price mentioned in the DGCIS data was not indicative of the PO price in Singapore as it showed (a) an extremely small volume being imported over a year, (b) wide discrepancy in unit PO prices from each country and (c) are not representative of the Asian market for PO. Refuting that import of subject goods from SEPL has adversely affected prices of the domestic industry, SEPL has charged that any alleged price under-cutting/ suppression could be due to the domestic industry's effort to retain its monopolistic position in the market and offer low prices to drive out competitors. They had exported FSP to India higher than its domestic prices in Singapore and for profit.

100. DPF has pointed out that the subject matter of the sunset review was imports of polyol, not PO. The volume and imports of PO could not form the basis of a determination whether AD duties should continue on polyol, the more so when there are imports of polyol during the POI and some exporters were cooperating with the Authority in the determination of normal value of polyol. Even if the normal value is constructed, the raw material price would be those in the exporting country, not the import price into India.

## J.2 Examination by the Authority

101. The domestic industry has not substantiated its claim of likelihood of dumping and injury, apart from data on imports of raw material prices. Post disclosure, the domestic industry has put the onus for this on the interested parties and the Authority. In addition, the domestic industry has claimed that in a sunset review, the Authority has to make a proper assessment and reach a conclusion that there is no possibility of any injury to the domestic industry from the dumped imports if duties are revoked and that significant price underselling was good reason for extension of duty.

102. The Authority observed that in the current scenario, the volume of the imports from the subject countries recorded a very significant jump in the POI, crowding out imports from other countries. However, despite the significant increase in imports, the domestic industry has maintained its market share in the POI, so that there is no current injury. Besides, the domestic industry's capacity is just about half the domestic demand, so that imports are inevitably required to meet the shortfall. The Authority also took cognizance of the fact that no increase in capacity has been effected during the injury period. As regards the effect of subject country imports on prices, there is no price undercutting, price-suppression or price depression. There is price under selling of 19% in the POI, based on the Supreme Court orders for computing NIP, which is much higher than the industry's own assessment.

103. In assessing the likely scenario, country-wise analysis of import data and prices shows the following highlights:

- ❖ The Authority notes that the imports from USA are entering at dumped prices even after imposition of duty as the dumping margin during the POI has been found to be significant. The trend in import prices show that CIF price of US imports has shown a rising trend, from 100 in 2003-04 (nil imports in 2002-03) to 134 in the POI, but as the customs duty over the injury period declined from 30% in 2002-03 to 14.5% in the POI, the trend in the landed value has registered a lower increase to 128 in the POI. Yet the landed value was progressively higher than the reference price of \$ 1597.49 per MT in 2004-05 and the POI. Though the landed price of the subject product in the POI is much higher than the reference price determined in the original investigation, the imports of the basic raw material from USA viz., propylene oxide which constitutes about 80% of the total cost of the subject goods, are at a higher CIF price in the POI than subject product imports. This implies existence of current dumping and likelihood of continued dumping. Besides, the trend in the quantity of imports from USA shows a tremendous increase from 100 in 2003-04 to 7250 in the POI. Therefore, the Authority is of the view that the dumped imports would likely to continue from USA in the event of withdrawal of duty.
- ❖ In the case of EU, the current dumping margin is negligible. But the dumped imports have continued and the quantity has increased. The indexed CIF price over the injury period moved from 100 to 126, while the landed value (indexed)

moved from 100 to 111. However, the landed value has remained above the reference price by a considerable margin in every year of the injury period. As regards the rate of the raw material imports from the EU, the data shows abnormally high rates, compared to other countries. The analysis shows that while the average CIF rate of imports of PO were substantially below the subject product prices in the early three years of the injury period, the situation is reversed in the POI. However, the isolated trend for one year does not give a clear indication of the price trend of PO and the subject goods from the EU. Therefore, considering the fact that the price from the EU has remained significantly above the reference price fixed for that country for the entire injury investigation period there is less likelihood of the trend getting reversed if the duty is removed. Therefore, the Authority is of the view that there is less likelihood of an imminent intensification or recurrence of dumping from EU if the duty is removed.

- ❖ In the case of Singapore, the Authority notes that the current dumping margin of the cooperating exporters have been determined to be negative on the basis of a single country specific normal value determined in pursuance to Supreme Court Judgment. The residual dumping margins determined on the above basis also works out to be negligible. However, the price of imports from Singapore indicates that the CIF price moved from 100 to 170 and the landed value from 100 to 150 during the injury period. But the landed value was below the reference price in the first two years of the injury period, and the prices have moved up above the reference price in 2004-05 and the POI only. As far as the raw material rates are concerned, in the POI, the PO imports from Singapore shows abnormal trend. The price trends of the subject goods during the POI and the basic raw material export price from the same country indicates that the price trend during the POI may not be sustainable or is not of permanent nature. The Authority further notes that the growth of imports from Singapore has been from 100 in 2002-03 to 3000 in the POI. Also the production capacities of the subject product of the co-operating producer/exporter are huge and should a shift in the direction of trade in the subject product occur in the exporting country, the growing domestic demand would attract a greater share of imports. Therefore, the Authority is of the view that there is a likelihood of recurrence of dumping, from this country once the duties are removed.
- ❖ As for Japan, in the absence of adequate data, no assessment could be made. For the two years for which data was available, in one year, the landed value was below, and in the other year, it was above, the reference price. The trend in propylene prices moved from 100 to 154. The rate of subject product imports in 2003-04 was higher than the raw material import rate by Rs 4000, but this difference narrowed to Rs 800 in 2004-05. The trend in the quantity of imports increased from 100 in 2003-04 to 550 in the next year. The export price of 2004-05 was extrapolated into the POI, using average growth in export price of the subject countries. The extrapolated data indicates the likely export price from Japan going by their price trend in the previous years and that likely export price when compared with the constructed normal value shows significant dumping

margin and injury margin. Therefore, the Authority is of the view that there is an imminent likelihood of recurrence of dumping from Japan in the event of withdrawal of duty.

104. In sum, the country-wise current and prospective scenarios are thus:

- ❖ USA: There exists current dumping and likelihood of continuation of dumping and consequential injury to the domestic industry;
- ❖ EU: There exists negligible current dumping and less likelihood of intensified dumping and consequential injury to the domestic industry;
- ❖ Singapore: There is negligible current dumping, but likelihood of intensification of dumping and consequential injury to the domestic industry;
- ❖ Japan: There is inadequate data to make an exact assessment, but likelihood of recurrence of dumping seems indicated, based on extrapolation of export price.

#### **K. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS**

105. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate injury to the domestic industry caused by the unfair trade practice of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market in the interests of the country. Though anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and thereby have some impact on their relative competitiveness, their imposition would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affected the availability of the products to the consumers.

#### **L. CONCLUSIONS:**

106. After examining the issues raised and based on the analysis of current dumping and injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- i) The subject goods have entered from USA at less than its normal value and the dumping margin of the subject goods imported are significant; while current dumping margins of subject goods imports from the European Union and Singapore are negligible.
- ii) There is a likelihood of dumping to continue from USA and of intensification or recurrence of dumping from Singapore and Japan if the duties are revoked; there is less likelihood of intensification of imports from the EU if duties are withdrawn.
- iii) The domestic industry suffers insignificant material injury at present due to the dumped imports; but there is a likelihood of recurrence of injury if duties are withdrawn.
- iv) Therefore, continued imposition of anti dumping duty is warranted against subject goods originating in or exported from USA, to offset dumping and against Singapore and Japan to prevent recurrence of dumping.

**M. RECOMMENDATIONS**

107. Having conducted the review and concluded that there is a likelihood of continuance and/or recurrence of dumping from the subject countries and consequent injury to the domestic industry, the Authority is of the opinion that continuation of the measure is required against imports from three of the four subject countries. However, considering the current level of dumping from the subject countries and injury suffered by the domestic industry, the Authority is of the opinion that the measure in force needs to be revised. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend continued imposition of the anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country, in terms of Section 9A(5) of the Act, in the form and manner described hereunder.

108. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends continued imposition of definitive anti-dumping duty equal to the margin of injury or dumping, which is lesser to remove the likelihood of injury to the domestic industry. Considering that the duty in the original investigation was imposed on reference price basis the Authority recommends continuation of definitive antidumping duty, on all imports of subject goods originating in or exported from USA, Singapore and Japan, as the difference between the landed value and the reference price as indicated in Col 9 of the table below, if the landed value at the time of importation is below the value indicated at Col.9. For the purpose of this landed value of imports will be determined as the value of the goods as assessed by Customs plus applicable basic Customs duty.

S.N o.	Sub- Head -ing/ Tariff Item	Descriptio n of Goods	Specificatio ns	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Reference price	Unit of Measur ement	Curren cy
1	3907.20	Flexible slabstock polyol	Molecular weight 3000- 4000	United States of America	Any	Any	Any	2420.36	MT	US D
2	-do-	-do-	-do-	Any except Japan and Singapore	United States of America	Any	Any	2420.36	MT	US D
3	-do-	-do-	-do-	Japan	Any	Any	Any	2391.98	MT	US D
4	-do-	-do-	-do-	Any except USA and Singapore	Japan	Any	Any	2391.98	MT	US D
5	-do-	-do-	-do-	Singapore	Any	M/s Shell Eastern Petroleum	Any other than M/s Shell Eastern Petroleum and M/s BASF South East Asia	1921.15	MT	US D
6	-do-	-do-	-do-	Singapore	Any	Any other than M/s Shell Eastern Petroleum	M/s BASF South East Asia	1942.29	MT	US D
7	-do-	-do-	-do-	Singapore	Any	Any other than M/s Shell Eastern Petroleum	Any other than M/s Shell Eastern Petroleum and M/s	2023.10	MT	US D

							BASF South East Asia			
8	-do-	-do-	-do-	Any except USA, EU and Japan	Singapore	Any	Any other than M/s Shell Eastern Petroleum and M/s BASF South East Asia	2023.10	MT	US D

**N. FURTHER PROCEDURE:**

109. Any appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

110. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time limit stipulated for this purpose.

R. GOPALAN, Designated Authority